Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 10
अंक : 258
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.00
बुधवार, 24 सितम्बर, 2025

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

3 अमेज़न के सामाजिक उत्तरदायित्व कोष से ...

4 भारत में गरीबी और अशिक्षा का आंकड़ा ...

7 डब्ल्यूएफआई ने अमन सहरावत को जारी ...

नवरात्रि का तीसरा दिन

मां चंद्रघंटा

नवरात्रि की तीसरी शक्ति है मां चंद्रघंटा. तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है. इन्हें पापों की विनाशिनी कहा जाता है. मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की उपासना से साहसी और पराक्रमी बनने का वरदान मिलता है. इस साल मां चंद्रघंटा की पूजा 17 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन होगी.

कैसे पड़ा मां चंद्रघंटा का नाम ?

मां दुर्गा का तीसरा रूप हैं मां चंद्रघंटा। युद्ध मुद्रा में सिंह पर विराजमान मां चंद्रघंटा के इनके हाथों में तलवार, त्रिशूल, धनुष व गदा धारण हैं। इनके माथे पर घंटे के आकार में अर्द्ध चंद्र विराजमान है, इसलिए ये चंद्रघंटा कहलाती हैं।मां चंद्रघंटा तंभ साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है और ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। शास्त्रों के अनुसार, मां चंद्रघंटा ने राक्षसों के संहार के लिए अवतार लिया था। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियां समाहित हैं।

मां चंद्रघंटा की पूजा विधि

मां चंद्रघंटा की पूजा में लाल और नारंगी रंग का अधिक प्रयोग करें। नवरात्रि के तीसरे दिन मणिपुर चक्र पर 'रं' अक्षर का जाप करने से मणिपुर चक्र मजबूत होता है। इससे मंगल के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। माता रानी को लाल चंदन, लाल चुनरी, लाल फूल और लाल फल(सेब) अर्पित करें। देवी दुर्गा के हर रुप को विशेष प्रसाद चढ़ाया जाता है। मां चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं और फिर देवी की आरती करें। इस तरह मां चंद्रघंटा की पूजा करने से साहस के साथ सौम्यता और विनम्रता में वृद्धि होती है

मां चंद्रघंटा का मंत्र

ऐं श्रीं शक्तयै नमः
या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमो नमः।।
पिण्डजप्रवरारूढ़ा ण्डकोपास्त्रकेर्युता। प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघण्टेति विश्रुता?

मां चंद्रघंटा के उपाय

नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के समक्ष एक छोटे लाल वस्त्र में लौंग, पान, सुपारी रखकर मां के चरणों में चढ़ाएं और देवी के नवार्ण मंत्र का 108 बार जाप करें। मां चंद्रघंटा के बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अगले दिन ये लाल पोटली सुरक्षित स्थान पर रख दें। जब भी किसी शुभ कार्य के लिए जाएं या फिर कोर्ट कचहेरी से संबंधित मामलों से जुड़ा कोई कार्य हो तो इस पोटली को साथ रखे। कहते हैं इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और शत्रु की हर चाल नाकाम होती है।

प्रधानमंत्री 75 लाख महिलाओं के खाते में भेजेंगे 10 हजार रुपये की राशि, 26 सितंबर को जारी होने जा रही पहली किस्त

पटना। सरकार ने बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक पात्र महिला को स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए 10 हजार रुपये की सहायता राशि मुहैया कराई जाएगी। योजना की विधिवत शुरुआत 26 सितंबर (शुक्रवार) को होने जा रही है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इसमें सूबे की 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये की राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) सीधे स्थानांतरण किए जाएंगे। इन महिलाओं के बीच साढ़े सात हजार करोड़ रुपये का वितरण किया जाएगा।

इस कार्यक्रम को आयोजित करने को लेकर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने इसे लेकर सभी जिलों के डीएम को पत्र जारी किया है। इसमें खासतौर से यह निर्देश दिया गया है कि इस मौके पर संकुल स्तरीय संघ ग्राम संगठन स्तर पर इसे उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर को उत्सव के तौर पर मनाने

एवं जन-जन तक इसकी जानकारी पहुंचाने के साथ ही महिला समूहों एवं सामुदायिक संगठनों को जागरूक करने के उदेश्य से राज्य मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जीविका स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों की सहभागिता होगी। योजना का लाभ लेने के लिए अब तक शहरी और ग्रामीण इलाकों की 1 करोड़ 11 लाख 66 हजार महिलाओं ने आवेदन किया है।

यह होगी कार्यक्रम की रूपरेखा

इस कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित की गई है। सभी 38 जिला मुख्यालय में डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें जन प्रतिनिधि के अलावा जिला स्तरीय अधिकारी एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी कम से कम 1 हजार महिलाएं भाग लेंगी।

ाभी 534 प्रखंड मुख्यालय में बीडीओ (प्रखंड विकास पदाधिकारी) की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम होगा। इसमें प्रखंड स्तरीय जन प्रतिनिधि, अधिकारी और एसएचजी से जुड़ी 500 महिलाएं भाग लेंगी।

जीविका के सभी 1680 संकुल स्तरीय संघ पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें संकुल स्तरीय जीविका समूह की 200 महिलाएं शामिल होंगी।

जीविका के सभी 70 हजार ग्राम संगठन स्तर पर भी इस कार्यक्रम के लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। इसमें एसएचजी से जुड़ी 100 महिलाएं भाग लेंगी।

यह है योजना का मकसद

यह राशि महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने, छोटे-मोटे व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसायों को बढ़ाने में सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता से महिलाएं खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई, और अन्य लघु उद्यमों में निवेश कर सकेंगी। स्वरोजगार शुरू कर महिलाएं स्वालंबी बन सकेगी। इससे इनका परिवार भी सशक्त बन सकेगा। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को समान रूप से लाभ पहुंचाना है।

राहुल का भाजपा पर वार

'वोट चोरी और बेरोजगारी एक-दूसरे से जुड़े, अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे युवा'

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब तक देश में चुनाव ईमानदारी से नहीं होंगे और वोट चोरी होती रहेगी, तब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ेगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर हिंदी में पोस्ट करते हुए लिखा कि आज के समय में भारत के युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और यह सीधे-सीधे वोट चोरी से जुड़ी हुई है।

जब कोई सरकार जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में आती है, तो उसका पहला कर्तव्य होता है युवाओं को रोज़गार और अवसर देना।

राहुल गांधी ने कहा, 'जब कोई सरकार जनता का भरोसा जीतकर सत्ता में आती है, तो उसका पहला कर्तव्य युवाओं को रोजगार और अवसर उपलब्ध कराना होता है। लेकिन भाजप ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतती।

अमित शाह ने 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान से जोड़ा भावनात्मक संदेश, गांधीनगर में किया वृक्षारोपण

गांधीनगर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) द्वारा 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत आयोजित वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया और लोगों से पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय योगदान देने का आग्रह किया। यह अभियान प्रतीकात्मक रूप से लोगों को अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

इससे पहले, 19 सितंबर को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा उनके जन्मदिन पर विशेष उपहार के रूप में भेंट किया गया एक कदम्ब का पौधा लगाया। दोनों देशों के बीच मित्रता और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति साझा प्रतिबद्धता का

प्रतीक यह पौधा, राजा चार्ल्स ने प्रधानमंत्री को बुधवार, 17 सितंबर को उनके 75वें जन्मदिन पर भेंट किया था। राजा चार्ल्स द्वारा भेंट किया गया कदम्ब का पेड़ 'एक पेड़ माँ के नाम' पहल से प्रेरित था। बुधवार को, ब्रिटिश उच्चायोग ने एक्स पर एक पोस्ट में इस उपहार के बारे में विवरण साझा करते हुए कहा, 'महामहिम राजा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर एक कदम्ब का पेड़ भेंट करके अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी की 'एक पेड़ माँ के नाम' पहल से प्रेरित यह भाव पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून, 2024 को दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में एक पीपल का पेड़ लगाकर की थी। यह पहल पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी को माताओं के प्रति सम्मान के साथ जोड़ती है।

सीएम स्टालिन बोले- अगर आठ साल पहले उएऊ में सुधार होता, तो लाखों करोड़ रुपये और बचा पाती जनता

चेन्नई।तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में बदलाव आठ साल पहले किया गया होता, तो देशभर के परिवार लाखों करोड़ रुपये और बचा सकते थे।

प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहा था कि जीएसटी में सुधार और आयकर में राहत से भारतीयों को ढाई लाख करोड़ रुपये की बचत होगी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए स्टालिन ने कहा, यही तो शुरुआत से विपक्ष की मांग थी। अगर ये कदम आठ साल पहले उठाए गए होते, तो देश के परिवार अब तक कई लाख करोड़ रुपये और बचा चुके होते।

स्टालिन ने यह भी कहा कि इस राहत का 50 फीसदी हिस्सा राज्य सरकारों ने वहन किया है। लेकिन केंद्र सरकार ने न तो इसका जिक्र किया और न ही इसे स्वीकार किया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है।

देश में 22 सितंबर से जीएसटी सुधारों को लागू किया गया है, जिसे 'जीएसटी बचत उत्सव' कहा जा रहा है। इसके तहत पहले की 5इ, 12इ, 18इ और 28इ की चार स्लैब वाली व्यवस्था को आसान बनाकर अब सिर्फ दो स्लैब 5इ और 18इ में बांटा गया है।

नवरात्रि की शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री ने 22 सितंबर को देशवासियों को एक खुला पत्र लिखते हुए कहा था, हमने मध्यम वर्ग को ताकत दी है। अब 12 लाख रुपये सालाना तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा।

बिहार चुनाव से पहले पटना में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी का महामंथन, राहुल-खड़गे करेंगे रणनीति तैयार!

पटना। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की एक महत्वपूर्ण बैठक की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। यह बैठक कथित वोटों की हेराफेरी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के बीच हो रही है, जिसके तहत देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। राज्य के राजनीतिक महत्व को देखते हुए, आगामी बिहार चुनाव चर्चा का एक प्रमुख विषय होने की उम्मीद है।

वेणुगोपाल ने एएनआई को बताया कि हम पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक कर रहे हैं, यह बैठक चुनाव से संबंधित नहीं है... हम ऐसा अक्सर कर रहे हैं। चर्चा के लिए कई मुद्दे हैं... वोटों की चोरी के खिलाफ एक राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है। देश भर में एक हस्ताक्षर अभियान भी चल रहा है... इसलिए हमें कई अन्य राजनीतिक मुद्दों के अलावा इस पर भी चर्चा करनी होगी। निश्चित रूप से, बिहार चुनाव चर्चा का विषय होगा।

कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक पटना स्थित पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में होगी। इस बैठक में

पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष राजेश राम, पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, राज्य विधायक दल के नेता शकील अहमद खान सहित कई नेताओं के शामिल होने की संभावना है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीडब्ल्यूसी बैठक की जानकारी दी और बताया कि पार्टी कथित 'वोट चोरी' और राज्य में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी और महंगाई जैसे कई मुद्दों पर चर्चा करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिहार में बिहार की बात तो करेगी ही, साथ ही राज्य में राष्ट्र की भी बात करेगी। बिहार में कई मुद्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे बेरोज़गारी, महंगाई, बढ़ता अपराध, महिलाओं के खलिफ़ अपराध, और ट्रंप के सामने युद्धविराम या आत्मसमर्पण। देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों के फ़ायदों पर चिंता जताते हुए, वेणुगोपाल ने कहा कि आम लोगों और ग़रीब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को मिलने वाले फ़ायदों के बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं है।

शिवकुमार बोले- सड़कों में गड्ढों के लिए कर्नाटक को निशाना बनाना ठीक नहीं, दिल्ली में भी ऐसी समस्या

बंगलूरू।कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि गड्ढों की समस्या केवल उनके राज्य की नहीं, ब्लकि पूरे देश की है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी शामिल है। उन्होंने मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि केवल कर्नाटक को ही इस समस्या के लिए बदनाम करना उचित नहीं है।

बंगलूरू के विकास मामलों के प्रभारी मंत्री शिवकुमार ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सड़कों की हालत सुधारे और वह इस पर काम कर रही है। उन्होंने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वह सत्ता में थी, तब उसने सड़कों की मरम्मत नहीं की और अब जब स्थानीय चुनाव नजदीक हैं, तो इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। शिवकुमार की यह टिप्पणी तब आई है, जब इंफोसिस के मुख्य वित्तीय अधिकारी मोहनदार पाई और बायोकॉन के प्रमुख किरण मजूमदार जैसे बंगलूरू के उद्योगपतियों ने सरकार से अपील की है।

मान सरकार की बड़ी सौगातः

पंजाब के लोगों को 10 लाख तक मुफ्त इलाज, सिर्फ आधार-वोटर कार्ड अनिवार्य

चड़ीगढ़। पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बलबीर सिंह ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य में नागरिकों के लिए 10 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत परिवार के सभी सदस्यों के लिए व्यक्तिगत कार्ड बनाए जाएँगे।

बलबीर सिंह ने बताया कि इस योजना के लिए आय या किसी अन्य लाभ का कोई मानदंड नहीं है; व्यक्ति के पास केवल पंजाब का आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र होना आवश्यक है।

बलबीर सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि प्रत्येक परिवार को 10,00,000 रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा मिलेगा... परिवार के सभी सदस्यों के लिए व्यक्तिगत कार्ड बनाए जाएँगे... आय या किसी अन्य चीज़ का कोई मानदंड नहीं है; व्यक्ति को केवल पंजाब का आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र चाहिए। मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत, लोग बिना किसी तनाव या कर्ज़ के सर्वश्रेष्ठ केंद्र पर इलाज करा सकते हैं, जिसमें कॉस्मेटिक सर्जरी को छोड़कर सभी

जीवन रक्षक प्रक्रियाएँ शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह योजना 2 अक्टूबर को शुरू होगी, जिसके लिए पंजीकरण शुरू हो गया है।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि इसकी शुरुआत तरनतारन और बरनाला से होगी... लोग बिना किसी तनाव या कर्ज़ के सर्वश्रेष्ठ केंद्र में इलाज करा सकेंगे... कॉस्मेटिक सर्जरी को छोड़कर, सभी जीवन रक्षक प्रक्रियाएँ इसमें शामिल हैं... प्रत्येक परिवार को हर साल 10,00,000 रुपये मिलेंगे; कोई अतिरिक्त राशि नहीं ली जाएगी... वोटर कार्ड और आधार कार्ड दोनों अनिवार्य हैं... योजना 2 अक्टूबर से शुरू होगी... पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत पंजाब का प्रत्येक परिवार 10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज के लिए पात्र होगा। इस पहल के बारे में बोलते हुए, मान ने कहा कि इसका लाभ 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कार्ड' के माध्यम से प्रदान किया जाएगा, जिसकी पंजीकरण प्रक्रिया कल से शुरू होगी।

कैट में सेवानिवृत्त नौकरशाह सरकार के खिलाफ आदेश देने में हिचकिचा रहे; भारी पड़ा कानूनी शुल्क का बोझ!

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वरिष्ठ ट्रेड यूनियन नेता सी. श्रीकुमार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति बीआर गवई की स्पष्ट टिप्पणियों का स्वागत किया है। मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के 10वें वार्षिक सम्मेलन में उसके कामकाज पर चिंता जताई थी। सीजेआई ने कहा, कई प्रशासनिक सदस्य, अक्सर सेवानिवृत्त वरिष्ठ नौकरशाह, सरकार के खिलाफ आदेश देने से हिचकिचाते हैं। वे इस जिम्मेदारी को उच्च न्यायालयों पर डालना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की अनिच्छा के कारण कैट के फैसलों के खिलाफ कई अपीलें दायर की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनावश्यक मुकदमेबाजी और न्याय मिलने में लंबी देरी हो रही है। सी. श्रीकुमार, जो 1985 में न्यायाधिकरण की स्थापना के बाद से सरकारी कर्मचारियों की ओर से मुकदमे लड़ रहे हैं, ने मुख्य न्यायाधीश के बयान का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने कहा, 'कैट' के कुछ प्रशासनिक सदस्य यह भूल जाते हैं कि वे अब नौकरशाह नहीं रहे। वे एक न्यायिक मंच पर बैठते हैं, जहां उनसे बिना किसी भय या पक्षपात के न्याय करने की अपेक्षा की जाती है। दुर्भाग्य से, कई लोग अभी भी अपनी सरकार समर्थक मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मुकदमेबाजी का पूर्व अनुभव न रखने वाले कुछ न्यायिक सदस्य भी सेवा मामलों की पेचीदगियों को समझने में संघर्ष करते हैं।

श्रीकुमार ने कहा, इससे अक्सर अनावश्यक देरी होती है और सरकार को कर्मचारियों के अभ्यावेदनों का एक निश्चित समय सीमा के भीतर निपटारा करने के लिए नियमित निर्देश दिए जाते हैं। इस बीच, कर्मचारियों पर भारी कानूनी शुल्क का बोझ पड़ता है। लंबित मामलों की चिंताजनक स्थिति की ओर इशारा करते हुए, श्रीकुमार ने बताया कि कैट के समक्ष 12 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं। उन्होंने इस संख्या के लिए कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों के प्रति सरकार और उसकी नौकरशाही की उदासीनता को जिम्मेदार ठहराया।

कर्नाटक जाति जनगणना पर बवालः

भाजपा सांसद बोले- सभी समुदायों में डर, असंतोष!

बैंगलुरू। भाजपा सांसद लहर सिंह सिरोया ने मंगलवार को जाति जनगणना की घोषणा को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की आलोचना की और आरोप लगाया कि इससे विभिन्न समुदायों और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी असंतोष पैदा हुआ है।एक्स पर एक पोस्ट में, सिरोया ने लिखा कि सिद्धारमैया ने इतनी जल्दी में जाति जनगणना का आदेश देकर, अपनी पार्टी के लोगों और कैबिनेट सहयोगियों सहित सभी को नाखुश कर दिया है। आज की स्थिति में, वोक्कालिगा, लिंगायत, दलित, ओबीसी, ब्राह्मण, अल्पसंख्यक, आदिवासी और खानाबदोश कांग्रेस सरकार से नाराज़ हैं। मुख्यमंत्री को पूछना चाहिए कि क्या उनका अपना कुरुबा समुदाय उनके साथ है या वे भी नाराज़ हैं। जाति सर्वेक्षण से वास्तव में कौन खुश है, यह पूछना एक अच्छा सवाल है। शायद केवल श्री राहुल गांधी।

सिरोया ने आगे कहा कि कर्नाटक के जाति सर्वेक्षण ने सभी समुदायों में भय पैदा कर दिया है, कोई भी समूह अपेक्षित परिणामों से संतुष्ट नहीं है, और चेतावनी दी कि सिद्धारमैया का नेतृत्व कांग्रेस को कमजोर कर सकता है, जिससे डीके शिवकुमार के लिए विरासत में बहुत कम

बचेगा। उन्होंने लिखा, 'कर्नाटक में हर समुदाय ने जाति सर्वेक्षण के खलिफ़ अपनी-अपनी नाराज़गी जताई है। हर समुदाय सर्वेक्षण के अंतिम नतीजों से डरा हुआ है। अब ऐसा लग रहा है कि कोई भी सर्वेक्षण उनकी आकांक्षाओं या उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। स्थानीय अखबार इन खबरों से भरे पड़े हैं। ऐसा लगभग लग रहा है कि श्री सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देंगे, और समय आने पर श्री डी.के. शिवकुमार के लिए कमान संभालने के लिए कुछ नहीं बचेगा।' उन्होंने कहा, 'खैर, भाजपा में हमें इस सब पर कोई शिकायत नहीं है। मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि जब केंद्र सरकार ने आम जनगणना के साथ-साथ सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है, तो राज्य सरकार को अलग से जाति सर्वेक्षण कराने की कोई ज़रूरत नहीं है।' उन्होंने कहा कि जाति सर्वेक्षण और घोटालों को लेकर सिद्धारमैया का तनाव मैसूर दशहरा समारोह में उनके सार्वजनिक आक्रोश में दिखा, जहाँ उन्होंने भीड़ को जल्दी चले जाने के लिए डाँटा।

सिरोया ने एक्स पर लिखा कि यह तथ्य कि सिद्धारमैया जाति सर्वेक्षण के संबंध में एक कठिन परिस्थिति में फंस गए हैं और बड़े घोटालों का बोझ उनके दिल पर भारी पड़ रहा है, यह सब उनके सार्वजनिक व्यवहार में झलक रहा है।

भारतीय नौसेना को मिलेगी नई ताकत, समंदर में गरजेगा दूसरा ASW युद्धपोत 'एंड्रोथ'

विशाखापत्तनम। भारतीय नौसेना इस वर्ष 6 अक्टूबर को विशाखापत्तनम स्थित नौसेना गोदी में अपने दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान , एंड्रोथ का जलावतरण करेगी। इस समारोह की अध्यक्षता पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर करेंगे, जो ASW-SWC श्रृंखला के सोलह जहाजों में से दूसरे जहाज के औपचारिक रूप से शामिल होने का प्रतीक है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता द्वारा 80इ से अधिक स्वदेशी घटकों के साथ निर्मित, एंड्रोथ सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण और रक्षा निर्माण में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। जहाज उत्पादन निदेशालय के मार्गदर्शन में और कोलकाता स्थित युद्धपोत निरीक्षण दल की देखरेख में निर्मित, यह जहाज 13 सितंबर 2025 को नौसेना को सौंप दिया गया। लक्षद्वीप द्वीपसमूह में एंड्रोथ द्वीप के नाम पर रखा गया यह जहाज अपने समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नया एंड्रोथ अपने पूर्ववर्ती आईएनएस एंड्रोथ (पी69) की विरासत को आगे बढ़ाता है, जिसने सेवामुक्त होने से पहले 27 वर्षों से अधिक समय तक नौसेना की सेवा की थी।

उन्नत हथियारों और सेंसर सूट, आधुनिक संचार प्रणालियों और जल जेट प्रणोदन से लैस, यह जहाज पानी के भीतर के खतरों का पता लगा सकता है, उन पर नज़र रख सकता है और उन्हें बेअसर कर सकता है, साथ ही समुद्री निगरानी, खोज और बचाव, और तटीय रक्षा अभियान भी चला सकता है। इसका जलावतरण भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को मज़बूत करता है और स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए विश्व स्तरीय युद्धपोतों पर देश के ध्यान को और मज़बूत करता है।

मराठवाड़ा में 50 साल की सबसे भारी बारिश, 8 लोगों की मौत, 159 गांव बाढ़ की चपेट में आए

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त मराठवाड़ा क्षेत्र में पिछले चार दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे आठ लोगों की मौत हो गई है और धाराशिव जिले के 159 गाँवों में बाढ़ आ गई है। अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र में 50 वर्षों से भी अधिक समय से इतनी भारी बारिश नहीं हुई है। 750 से ज़्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, 186 मवेशी मारे गए हैं, जबकि 33,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की फ़सलें नष्ट हो गई हैं। भारी बारिश के कारण जालना और बीड में तीन पुल, छत्रपति संभाजीनगर में दो स्कूल और मराठवाड़ा में पाँच छोटे बाँध भी ढह गए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने आपदा की गंभीरता को देखते हुए कहा, 'स्थिति बहुत गंभीर है। पिछले 50-70 सालों में इतनी बारिश कभी दर्ज नहीं की गई। पूरे महाराष्ट्र में 63.51 लाख एकड़ कृषि भूमि नष्ट हो गई है, जिससे कृषि क्षेत्र

गाँव पानी में डूब गए हैं। उपजाऊ मिट्टी बह गई है और किसानों की फसलें और मवेशी बर्बाद हो गए हैं।

कृषि मंत्री दत्तात्रेय भारणे ने बताया कि में हुए नुकसान का स्तर स्पष्ट होता है। जयकवाड़ी और माजलगाँव बाँधों के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण अधिकारियों को पानी छोड़ना पड़ा, जिससे छत्रपति संभाजीनगर, जालना और बीड में नदियाँ और उफान पर आ गईं और बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धाराशिव और बीड में चल रहे बचाव कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) ने धाराशिव में 27 लोगों को बचाया है और 200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है।

1 जून से मराठवाड़ा में औसत से 28.5 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है, जिसमें धाराशिव में सामान्य से 148 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है। सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए 2,215 करोड़ रुपये की घोषणा की है, जिनमें से 31.64 लाख किसानों को पहले ही सहायता मिल चुकी है। वहीं विपक्षी नेताओं ने प्रशासन की आलोचना की है और लंबे समय से फसल और मिट्टी के नुकसान का सामना कर रहे किसानों की मदद के लिए शीघ्र मुआवजे की मांग की है।

सनातन संस्था पर बैन लगाने की कोशिशों को झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट में वापस हुई याचिका

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक याचिकाकर्ता से पूछा, जिसने 2011 में दक्षिणपंथी समूह सनातन संस्था पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी, कि उसकी याचिका कैसे विचारणीय है। अदालत ने याचिकाकर्ता विजय नामदेव रोकड़े और अन्य से कहा कि या तो वे अपनी याचिका वापस ले लें, अन्यथा खारिज होने का सामना करें। निर्देशों के बाद, याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने जनहित याचिका वापस ले ली। याचिका में सनातन संस्था को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इसके सदस्य 'सम्मोहन और आतंकवादी गतिविधियों' में शामिल हैं। अदालत ने पहले भारत संघ और संस्था को याचिका पर जवाब

दाखिल करने का निर्देश दिया था। 2017 में भारत संघ ने अदालत को सूचित किया कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सामग्री केंद्र के लिए यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं थी कि संस्था की गतिविधियाँ आतंकवादी संगठन के रूप में योग्य हैं। अपने जवाब में सनातन संस्था ने आरोपों का पुरज़ोर खंडन किया और याचिकाकर्ताओं पर कड़ी सज़ा की माँग की। गोवा में संस्था के प्रबंध न्यासी वीरेंद्र मराठे द्वारा दायर जवाब में कहा गया कि याचिका याचिकाकर्ताओं की कल्पना की उड़ान पर आधारित है। आतंकवाद के आरोपों पर, संस्था ने कहा, 'संस्था के खिलाफ़ एक भी आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

ठाणे, वाशी और पनवेल में सिनेमाघरों को निशाना बनाकर किए गए विस्फोटों से जुड़े आरोपों पर हलफनामे में कहा गया है कि संगठन की जांच से पता चला है कि आरोपपत्र या उन कार्यवाहियों में पारित फैसले में कहीं भी सनातन संस्था के बारे में कोई जिक्र तक नहीं था।

अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में शीघ्र कार्रवाई की जाए- आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुइके

मुंबई। सरकार आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं और पहलों का क्रियान्वयन कर रही है। सरकार इस समुदाय के सशक्तिकरण के लिए सकारात्मक कदम उठा रही है। आरक्षण के अनुसार नौकरियों में इस समुदाय को प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए विभिन्न विभागों में अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में शीघ्र कार्रवाई की जाए, यह निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुइके ने मंत्रालय में आयोजित आदिवासी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की एक बैठक में दिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार आदिवासी समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक है।

बैठक में खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि जिरवाल, सांसद भास्कर भागरे, सांसद डॉ. हेमंत सावरा, विधायक सर्वश्री राजेंद्र गावित, आमशा पडवी, हीरामन खोसकर, डॉ. मिलिंद नरोटे, डॉ. किरण लाहमटे, शिरीष कुमार नाइक, विलास तारे, शांताराम मोरे, काशीराम पवारा, हरिश्चंद्र भोये, दौलत दरोदा, विधायक मंजुला गावित उपस्थित थे। साथ ही, सामान्य प्रशासन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वी. राधा, आदिवासी विकास विभाग के सचिव विजय वाघमारे, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव गणेश पाटिल भी उपस्थित थे।

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुइके ने कहा कि पेसा क्षेत्र में आरक्षण निर्धारण के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। समिति निर्धारित अवधि में सरकार को सिफारिशों सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन, 'पेसा' क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती करने की कार्रवाई की जाए। अनुसूचित जनजाति वर्ग में जाति वैधता प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी।

अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकांश पदों की जानकारी संकलित की जानी चाहिए। अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालयों में भर्ती को मंजूरी दे दी गई है। विद्यालयों को सामूहिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद इस भर्ती प्रक्रिया को लागू करना चाहिए, यह निर्देश भी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुइके ने दिए।

बैठक में आदिवासी आश्रम विद्यालयों में भोजन आपूर्ति के लिए केंद्रीय रसोई योजना, पट्टे पर भूमि, 'पेसा' क्षेत्र में भर्ती, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अधिकांश पद और जाति वैधता प्रमाण पत्र सत्यापन समितियों पर भी चर्चा हुई।

मध्य रेल के सोलापुर मंडल में स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के अंतर्गत 'आर्ट फ्रॉम वेस्ट' पर प्रदर्शनी का आयोजन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेल के सोलापुर मंडल ने चल रहे 'स्वच्छता ही सेवा - 2025' अभियान के अंतर्गत 22 सितंबर 2025 को सोलापुर के न्यू कोचिंग कॉम्प्लेक्स में 'आर्ट फ्रॉम वेस्ट' विषय पर एक अनूठी प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और अपशिष्ट प्रबंधन का संदेश फैलाते हुए, अनुपयोगी सामग्रियों के कम करने, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और रचनात्मक उपयोग के महत्व पर प्रकाश डालना था। प्रदर्शनी का उद्घाटन अपर मंडल रेल प्रबंधक (एडीआरएम) श्री अंशुमाली कुमार और वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता (सीनियर डीएमई) ने किया। इस अवसर पर, एडीआरएम द्वारा गुलाब के पौधे का प्रतीकात्मक रोपण भी किया गया, जो कचरे को सार्थक और जीवनदायी बनाने के विषय को दर्शाता है।

अपशिष्ट पदार्थों से तैयार की गई विभिन्न नवीन वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया। बेकार प्लास्टिक की पानी की बोतलों और रासायनिक डिब्बों को कलात्मक रूप से स्टेशनरी होल्डर, पक्षी फीडर, फूलों की टोकरियाँ, बहुउद्देशीय कंटेनर, टूलबॉक्स, पौधों के फूलदान और तेल की फ़नल में बदल दिया गया। ये सोफा, हाथी, मोर, कूड़ेदान, हेलमेट स्टैंड, टूलबॉक्स, रोबोट आकृतियाँ, पेड़ के गमले पकड़े हुए पुरुष और बहुत कुछ बनाया गया, जो रेलवे कर्मचारियों

की रचनात्मक भावना को प्रदर्शित करता है।

सी एंड डब्ल्यू डिपो, एसपीएआरएमवी (स्वचालित दुर्घटना राहत चिकित्सा वैन), और ट्रैक मशीन डिपो की टीमों ने प्रदर्शनी के दौरान सक्रिय रूप से भाग लिया और अपनी कृतियों का प्रदर्शन किया। डिपो प्रभारी श्री एस.ए. बसर्गी, एसएसई/ट्रैक मशीन श्री तिग्गा, एसएसई/ईएनएचएम श्री जितेंद्र वाघमारे और उनकी समर्पित टीमों के प्रयासों की प्रदर्शनी के सफल आयोजन के लिए विशेष रूप से सराहना की गई। प्रदर्शनी में सीएंडडब्ल्यू, इलेक्ट्रिकल और आरपीएफ कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों और अन्य आगंतुकों ने भाग लिया, और सभी ने प्रदर्शित रचनात्मकता और नवाचार की प्रशंसा की।

एडीआरएम और सीनियर डीएमई दोनों ने इस पहल की सराहना की और स्वच्छता ही सेवा की भावना के साथ तालमेल बिठाने के लिए ईएनएचएम (पर्यावरण एवं हाउसकीपिंग प्रबंधन) टीम और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की। इस प्रेरक प्रदर्शनी के माध्यम से, सोलापुर मंडल ने एक बार फिर स्थिरता और नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और यह साबित किया कि कल्पना और समर्पण से कचरे को भी चमत्कार में बदला जा सकता है।

डबलिन स्थित भारतीय दूतावास द्वारा असम को समर्पित पहला सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विविधता में एकता और 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना से प्रेरित होकर, डबलिन स्थित भारतीय दूतावास ने आयरलैंड में पहली बार असम राज्य को समर्पित एक विशेष सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया। यह आयोजन दूतावास की राज्य-सांस्कृतिक कार्यक्रम-श्रृंखला पहल का एक हिस्सा था।

इस कार्यक्रम में असम की समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पाककला और पर्यटन की विरासत पर एक मल्टीमीडिया प्रस्तुति के साथ-साथ कई पारंपरिक नृत्य, असमिया कविता पाठ और असम की आकर्षक वस्त्र एवं शिल्प परंपरा का प्रदर्शन शामिल था। यह कार्यक्रम श्री दिगंत मालाकार की अध्यक्षता वाले असम एसोसिएशन ऑफ़ आयरलैंड के उत्साही समर्थन और भागीदारी के कारण संभव हो सका।

इस अवसर पर बोलते हुए, आयरलैंड में भारत के राजदूत, महामहिम श्री अखिलेश मिश्र ने राजदूतावास द्वारा असम पर पहली बार आयोजित विशेष प्रस्तुति की मेजबानी पर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। यह कार्यक्रम आयरलैंड में, अपेक्षाकृत छोटे लेकिन अत्यंत जीवंत और सक्रिय असमिया समुदाय (जिनकी वर्तमान में अनुमानित संख्या लगभग 200 है) की ऊर्जा से ही सम्भव हुआ। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत के विभिन्न राज्यों की अपनी अपनी अपनी वशिष्ट भाषाई, सांस्कृतिक और प्राकृतिक आकर्षण, कला और शिल्प की विरासत है। सभी भारतीयों को भारत के अन्य भागों में रहने वाले अपने भाइयों और बहनों की सांस्कृतिक समृद्धि और रचनात्मक कौशल के बारे में जानने, पारस्परिक विकास के लिए एक-दूसरे से सीखने और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक-दूसरे की प्रगति और प्रसार में सहयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने याद दिलाया कि राजदूतावास की राज्य सांस्कृतिक कार्यक्रम श्रृंखला (जिसके अन्तर्गत अब तक 16 राज्यों को समर्पित कार्यक्रम किए जा चुके है) शुरू करने का मुख्य उद्देश्य आयरलैंड में प्रवासी भारतीयों के साथ-साथ आयरिश लोगों को भारत की अविश्वसनीय विविधता में विद्यमान एकता का अनुभव करना ही था।

राज्य की सड़कें गड्ढामुक्त और उच्च गुणवत्ता वाली होंगी- लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले

राज्य में सड़कों के वार्षिक रखरखाव और मरम्मत के लिए 1296.05 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। राज्य में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों के तत्काल रखरखाव और मरम्मत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने राज्य में सड़कों के वार्षिक रखरखाव और मरम्मत कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 1296.05 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी है, लोक निर्माण (सार्वजनिक उपक्रमों को छोड़कर) मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले ने यह जानकारी दी।

लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले ने कहा कि सड़कें राज्य की प्रगति की जीवनरेखा हैं। सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और गड्ढामुक्त सड़कों का निर्माण सरकार की प्राथमिकता है। इस निधि की स्वीकृति से न केवल तत्काल मरम्मत कार्य किए जा सकेंगे, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके इन कार्यों में पारदर्शिता भी लाई जा सकेगी। साथ ही, वृक्षारोपण और संरक्षण अभियान पर्यावरण-अनुकूल विकास को बढ़ावा देंगे। गड्ढा मुक्त, सुरक्षित और टिकाऊ सड़कें उपलब्ध होंगी। यात्रा समय और ईंधन की बचत होगी। दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। सड़कों के चारों ओर हरित पट्टी बनाई जाएगी और पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल उपकरण कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण प्रदान करेंगे।

इस निधि से राज्य की सड़कों को नया जीवन मिलेगा। इस राशि का उपयोग गड्ढों को भरने, तत्काल मरम्मत, बारिश से प्रभावित सड़कों की मरम्मत के साथ-साथ पूरक कार्यों के लिए किया जाएगा। एएमसी (वार्षिक रखरखाव अनुबंध) के तहत 43,043.06 किलोमीटर सड़कों के गड्ढे चरणों में भरे जाएँगे। इससे नागरिकों के लिए सुव्यवस्थित सड़कों पर सुरक्षित यात्रा करना आसान हो जाएगा।

राज्य के आठ क्षेत्रीय संभागों के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों की सड़कों की मरम्मत की जाएगी। प्रत्येक संभाग में कार्य समय पर पूरे हों, यह सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष योजना तैयार की गई है। सरकार न केवल मरम्मत कार्यों पर, बल्कि कार्यों की गुणवत्ता की जाँच और मानक प्रक्रियाओं के पालन पर भी कड़ी नज़र रखेगी।

सरकार ने सड़कों की मरम्मत समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से सुनिश्चित करने के लिए तकनीक का सहारा लिया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक एआई-आधारित ऐप विकसित किया गया है, जिसकी मदद से सड़कों पर गड्ढों की स्थिति, मरम्मत की स्थिति और कार्यों की प्रगति की वास्तविक समय में जाँच संभव होगी। इस ऐप के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिकों को कार्यों की प्रगति की जानकारी उपलब्ध होगी।

लोक निर्माण विभाग ने इस वर्ष से सड़कों के दोनों ओर, डिवाइडर पर और सरकारी भवनों के आसपास वृक्षारोपण का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक 'वृक्षारोपण एवं रखरखाव प्रणाली ऐप' विकसित किया गया है। इस ऐप की मदद से वृक्षारोपण की सटीक निगरानी की जा सकेगी और पेड़ों की देखभाल की नवीनतम जानकारी सरकार को तुरंत उपलब्ध हो सकेगी। इस पहल से न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा, बल्कि सड़कों की सुंदरता में भी वृद्धि होगी। लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले ने भी यह जानकारी दी।

संजय राउत का भाजपा पर तंज

'उपराष्ट्रपति बदल सकते हैं लेकिन पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे'

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने भाजपा पर तीखा हमला। उन्होंने सवाल उठाया कि आप देश के मुख्य न्यायाधीश से लेकर उपराष्ट्रपति और चुनाव आयुक्त तक को बदल सकते हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं? राउत ने कहा कि इस पूरे मामले पर किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं है और यही भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी है। राउत ने कहा कि भाजपा नेतृत्व आज संगठनात्मक चुनाव कराने में असमर्थ दिख रहा है। उन्होंने व्यंग्य किया कि जब सरकार सर्वोच्च संस्थानों के पदाधिकारियों को बदलने में सक्षम है, तो अपने संगठन प्रमुख के चुनाव से क्यों पीछे हट रही है। राउत के इस बयान को भाजपा की कार्यशैली और पारदर्शिता पर सीधा हमला माना जा रहा है।

मुंबई नगर निगम चुनाव की चर्चा

मुंबई महानगरपालिका चुनाव को लेकर राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच बातचीत सकारात्मक चल रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीटों के बंटवारे पर केवल तभी बयान दिया जाएगा जब सारी चर्चाएं पूरी होंगी। राउत ने संकेत दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार का असर बरकरार है और इसका प्रभाव आगामी चुनाव में दिखेगा।

मराठी पहचान और ठाकरे ब्रांड

राउत ने मराठी अस्मिता को भी मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि 'मराठी जनता दिखाएगी कि ठाकरे ब्रांड का असली मतलब क्या है।' उनका इशारा इस ओर था कि मुंबई और महाराष्ट्र में स्थानीय पहचान की राजनीति एक बार फिर निर्णायक साबित हो सकती है। शिवसेना (यूबीटी) और मनसे के बीच तालमेल की संभावना को लेकर भी उन्होंने उत्सुकता बढ़ाई।

शरद पवार भाजपा पर हमलावर

'चुनाव आयोग पर राहुल की टिप्पणियों पर बीजेपी की प्रतिक्रिया से बढ़ा अविश्वास',

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पुणे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि जब भी कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनाव आयोग (ईसीआई) के कामकाज पर सवाल उठाते हैं, तो जवाब देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सामने आते हैं। शरद पवार का कहना है कि इस तरह की प्रतिक्रिया चुनाव आयोग को लेकर जनता के मन में अविश्वास और संदेह पैदा करती है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

'आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल तो जवाब वही दे'

पुणे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, 'जब राहुल गांधी या विपक्ष के अन्य नेता चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाते हैं, तो यह आयोग की जिम्मेदारी है कि वह खुद सामने आकर जवाब दे। लेकिन हो यह रहा है कि आयोग चुप रहता है और भाजपा के नेता प्रतिक्रिया देते हैं। इससे लोगों में यह संदेश जाता है कि आयोग के बजाय सत्ता पक्ष ही उसकी ओर से बोल रहा है।' उन्होंने आगे कहा कि यह तरीका चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को कमजोर करता है और जनता के मन में यह शक पैदा करता है कि आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है या नहीं।

राहुल गांधी का वोट चोरी का आरोप

कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लोकतंत्र को खत्म करने वालों को बचाने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने दावा किया कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की दो विधानसभा सीटों के आंकड़ों से पता चलता है कि बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में हेराफेरी की गई। उनका आरोप था कि कुछ मतदाताओं के नाम गलत तरीके से सूची से हटाए गए और कुछ को धोखाधड़ी के जरिए जोड़ा गया, जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हुई। कांग्रेस नेता ने इस कार्रवाई को वोट चोरी करार देते हुए कहा कि यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है।

राहुल गांधी को चुनाव आयोग का जवाब

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को गलत और निराधार बताया।आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन वोटर लिस्ट से नाम न तो हटा सकता है और न ही जोड़ सकता है। राहुल गांधी के आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं और यह पूरी तरह गलतफहमी है।'

मध्य रेल
मुंबई मंडल
निविदा सूचना क्रमांक: आरआर/पीआर/एसएनपीडी/317/25-26/18
कार्य का विवरण: एम.पी.सी.बी. की सहमति के अनुसार ईएमयू पीओएच सानपाडा कार्यशाला में उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट का निपटान। **अनुमानित लागत:** रु. 1223915.37/-, **ईएमडी:** रु. 24500/-, **निविदा प्रपत्र का शुल्क:** कुछ नहीं, **समापन अवधि:** 24 महीना, **निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय:** 10/10/2025, 14:30 बजे तक, **बोली शुरू करने की तारीख:** 26/09/2025, टेंडर केवल ई-टेंडरिंग में वेबसाइट www.ireps.gov.in के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। टेंडर पंजिका वेबसाइट में उपलब्ध है।
SUN 483 सहायक कार्य प्रबंधक
असुरक्षित तथा अनाधिकृत रूप से रेल लाइन के पास कार्य करना दंडनीय अपराध है

अमेज़न के सामाजिक उत्तरदायित्व कोष से राज्य की प्रगति में योगदान- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

वीडियो सिस्टम के माध्यम से अमेज़न वेब सर्विसेज़ डेटा सेंटर का भूमिपूजन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। महाराष्ट्र देश में निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। स्विट्ज़रलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच में भी महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा निवेश लाया। इस मंच पर अमेज़न ने राज्य में 'क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर' क्षेत्र में भारी निवेश करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसी के अनुरूप अमेज़न निवेश कर रहा है। अमेज़न का निवेश राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण बना रहेगा और कंपनी का सामाजिक उत्तरदायित्व कोष राज्य की प्रगति में योगदान देगा, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने वर्षा के आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुंबई में अमेज़न वेब सर्विसेज़ कंपनी के डेटा सेंटर की आधारशिला रखी। अमेज़न वेब सर्विसेज़ कंपनी ने इस पहल के माध्यम से राज्य में अपने 8.3 बिलियन डॉलर के निवेश के पहले चरण की शुरुआत की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के निवेश सलाहकार कौस्तुभ धावसे, अमेज़न वेब सर्विसेज के वैश्विक उपाध्यक्ष (सार्वजनिक नीति) माइकल पुनके,

दक्षिण एशिया और भारत के अध्यक्ष संदीप दत्ता, एशिया प्रशांत क्षेत्र के निदेशक विक्रम श्रीधरन, भारत में कंपनी के बुनियादी ढाँचा क्षेत्र के निदेशक आदित्य चौधरी, साथ ही गायत्री प्रभु, शुभंकर दास, रीना मरांडा आदि उपस्थित थे।

इस अवसर पर, मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार उद्यमियों के लिए राज्य में उद्योग स्थापित करना आसान और सरल बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। उद्योगों द्वारा आवश्यक लाइसेंस की अवधि को कम करने और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' वॉर रूम के माध्यम से तेजी से कार्रवाई की जा रही है। उद्यमियों को अनुमति के लिए दिए गए प्रस्तावों की 'वास्तविक समय की जानकारी' प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है।

इस अवसर पर, अमेज़न ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अमेरिका के सिएटल में कंपनी के मुख्यालय का दौरा करने के लिए भी आमंत्रित किया। इस अवसर पर, राज्य में सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के माध्यम से बिजली, जलापूर्ति, शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही गतिविधियों की जानकारी दी गई।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने अमेज़न मोबाइल एऊिं लैब पहल के अंतर्गत भारत की पहली 'थिंक बिग मोबाइल वैन' को हरी झंडी दिखाई। यह वैन आधुनिक तकनीक की मदद से मुंबई शहर के छात्रों को विभिन्न शोध और नए विचारों से अवगत कराएगी।

जुलाई-अगस्त में आपदा प्रभावित किसानों के लिए 19.22 करोड़ रुपये

1,339 करोड़ रुपये की सहायता को मंज़ूरी- राहत एवं पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव-पाटिल

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

राहत एवं पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव-पाटिल ने जानकारी दी है कि जुलाई और अगस्त 2025 में राज्य में हुई भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित 19 लाख 22 हज़ार 909 किसानों की 15 लाख 45 हज़ार 250.05 हेक्टेयर भूमि पर फसलों के नुकसान के लिए 1,339 करोड़ 49 लाख 25 हज़ार रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है। इस संबंध में सरकारी निर्णय जारी कर दिया गया है।

राहत एवं पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव-पाटिल ने विश्वास व्यक्त किया कि इस मानसून के दौरान हुई भारी बारिश और बाढ़ के कारण किसान संकट में हैं और यह सहायता संकटग्रस्त किसानों को तत्काल सहायता प्रदान करने और उनके जीवन को आसान बनाने में निश्चित रूप से उपयोगी होगी।

अमरावती संभाग

अमरावती संभाग के अमरावती, अकोला, यवतमाल, बुलढाणा और वाशिम जिलों के 7 लाख 88 हजार 974 किसानों की 6 लाख 54 हजार 595.42 हेक्टेयर भूमि पर फसलों को हुए नुकसान के लिए 565 करोड़ 60 लाख 30 हजार रुपये की सहायता को मंजूरी।

नागपुर संभाग

नागपुर संभाग के गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, वर्धा और नागपुर जिलों के 37 हजार 631 किसानों की 21 हजार 224.64 हेक्टेयर भूमि पर फसलों को हुए नुकसान के लिए 23 करोड़ 85 लाख 26 हजार रुपये की सहायता को मंजूरी।

पुणे संभाग

पुणे संभाग के कोल्हापुर जिले में 36 हजार 559 किसानों की 8 हजार 835.15 हेक्टेयर भूमि पर फसलों को हुए नुकसान के लिए 14 करोड़ 28 लाख 52 हजार रुपये की सहायता को मंजूरी।

छत्रपति संभाजीनगर

छत्रपति संभाजीनगर संभाग के हिंगोली, बीड, लातूर और धाराशिव जिलों के 10 लाख 35 हजार 68 किसानों की 8 लाख 48 हजार 445.37 हेक्टेयर भूमि पर फसलों के नुकसान के लिए 721 करोड़ 97 लाख 86 हजार रुपये की सहायता को मंजूरी।

नासिक संभाग

नासिक संभाग के नासिक, धुले, नंदुरबार, जलगाँव और अहिल्यानगर जिलों के 24 हजार 677 किसानों की 12 हजार 149.46 हेक्टेयर भूमि पर फसलों के नुकसान के लिए 13 करोड़ 77 लाख 31 हजार रुपये की सहायता को मंजूरी दी गई है।

फसलों की बुवाई से लेकर बिक्री तक की प्रक्रिया को और अधिक समन्वित बनाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन - कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

फसलों की बुवाई से लेकर बिक्री तक की प्रक्रिया को और अधिक सुगम एवं समन्वित बनाने के लिए कृषि एवं विपणन विभाग का एक टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने कहा कि बुवाई से लेकर बिक्री तक किसानों को मार्गदर्शन प्रदान करने से कृषि आय में वृद्धि होगी और कृषि उत्पादों को बेहतर मूल्य प्राप्त होंगे। विपणन मंत्री जयकुमार रावल ने इस बैठक में विपणन एवं कृषि विभाग की परियोजनाओं का क्रियान्वयन और अधिक शीघ्रता से करने की मांग की।

विपणन एवं कृषि विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के समन्वय के संबंध में मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे बोल रहे थे। बैठक में विपणन मंत्री जयकुमार रावल, सहकारिता विभाग के सचिव प्रवीण दराडे, कृषि आयुक्त सूरज मंधारे, उप सचिव ए.एस. चंदनशिवे, अवर सचिव (विपणन) अस्मिता पाटिल, महाराष्ट्र कृषि विपणन बोर्ड के संयुक्त प्रबंधक विनायक कोकाटे, दूरदर्शन प्रणाली के माध्यम से स्मार्ट परियोजना के निदेशक हेमंत वासेकर, निदेशक (विस्तार) रफीक नायकवाड़ी, महाराष्ट्र राज्य गोदाम बोर्ड के प्रबंध निदेशक दीपक शिंदे, कृषि निदेशक सुनील बोरकर और कृषि विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कृषि मंत्री श्री भरणे ने कहा कि फसलों की बुवाई से वास्तविक उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि विभाग विभिन्न उपाय कर रहा है। किसानों को कौन सी फसल बोनी चाहिए जिससे बिक्री के बाद फसल का अधिक मूल्य मिले। मौसम पूर्वानुमान और कृषि उपज की बिक्री के बारे में मार्गदर्शन के लिए एक फसल मार्गदर्शन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। विपणन और कृषि विभाग के अधिकारी समन्वय से काम करें। स्मार्ट परियोजना के तहत साझेदारी के माध्यम से स्थापित किए जाने वाले गोदामों, समुदाय-आधारित संगठनों के साथ साझेदारी के माध्यम से विकेन्द्रीकृत गोदामों की स्थापना और समृद्धि महामार्ग-एग्रो लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के कार्य को पूरा करने में कृषि विभाग हर संभव सहायता प्रदान करेगा, ऐसा कृषि मंत्री श्री भरणे ने कहा।

पाँच लाख रुपये से अधिक लागत वाली नौ गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को मिलेगी धनराशि

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मरीजों के दावों से प्राप्त राशि का उपयोग राज्य स्वास्थ्य गारंटी सोसाइटी के आरक्षित कोष और सरकारी अस्पतालों के सशक्तीकरण के लिए किया जाएगा। साथ ही, जरूरतमंद मरीजों के लिए पाँच लाख रुपये से अधिक लागत वाली नौ प्रकार की दुर्लभ बीमारियों के इलाज का खर्च भी आरक्षित कोष से ही वहन किया जाएगा। इस संबंध में प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की।

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, राज्य स्वास्थ्य गारंटी सोसाइटी द्वारा सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों को धनराशि प्रदान की जाती है। इस निधि के उपयोग के संबंध में 11 जनवरी, 2019 को जारी दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है, जिसके तहत सोसाइटी से प्राप्त धनराशि का 20 प्रतिशत आरक्षित कोष में जाएगा। जबकि शेष 80 प्रतिशत संबंधित अस्पतालों को दिया जाएगा। इस 80 प्रतिशत निधि में से 19 प्रतिशत अस्पतालों में बुनियादी ढाँचे के निर्माण, 40 प्रतिशत अस्पताल में खुदरा सामग्री और दवाओं की बिक्री, 20 प्रतिशत अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रोत्साहन भत्ते और 1 प्रतिशत कार्यक्रम समर्थन सूचना एवं प्रचार-प्रसार पर खर्च किया जा सकेगा।

विस्तारित योजना में स्वास्थ्य बीमा की सीमा प्रति व्यक्ति प्रति परिवार 5 लाख रुपये है। हालाँकि, इस योजना के अंतर्गत दुर्लभ बीमारियों जैसे यकृत, अस्थि मज्जा, हृदय, फेफड़े आदि के उपचार के लिए स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध नहीं है, जिनकी लागत 5 लाख रुपये से अधिक है। इसलिए, इन बीमारियों का इलाज करा रहे गरीब और ज़रूरतमंद मरीज इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएँगे। हालाँकि, ऐसी नौ बीमारियों का खर्च राज्य स्वास्थ्य गारंटी सोसाइटी के पास बनी आरक्षित निधि से किया जाएगा।

इसमें हृदय प्रत्यारोपण के लिए 15 लाख रुपये, फेफड़े प्रत्यारोपण के लिए 20 लाख रुपये, हृदय और फेफड़े प्रत्यारोपण के लिए 20 लाख रुपये, यकृत प्रत्यारोपण के लिए 22 लाख रुपये, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण (एलोजेनिक) के लिए 9.5 लाख रुपये, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण (असंबंधित) के लिए 17 लाख रुपये, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण (हैप्लो) के लिए 17 लाख रुपये, ट्रांसकैथेटर महाधमनी वाल्व प्रत्यारोपण (टीएवीआई) के लिए 10 लाख रुपये और ट्रांसकैथेटर महाधमनी वाल्व प्रतिस्थापन (टीएमवीआर) के लिए 10 लाख रुपये शामिल हैं।

इस योजना के तहत, लोक स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं औषधि विभाग और नगरीय विकास विभाग के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के डॉक्टरों और कर्मचारियों के प्रोत्साहन भत्ते में संशोधन किया जाएगा, जो उपचार प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। इसके लिए, मंत्रिपरिषद ने प्रोत्साहन भत्ते के संबंध में 11 जनवरी, 2019 के सरकारी निर्णय में भत्ता सीमा की शर्त में छूट को भी मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमण्डल की बैठक में लोक स्वास्थ्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष उपचार सहायता एवं सशक्तीकरण समिति के गठन को भी मंजूरी दी गई, जो इस योजना के अंतर्गत शल्य चिकित्सा, उपचार और उनकी दरों में परिवर्तन, प्राप्त सरकारी धनराशि के आवंटन और आरक्षित निधियों की प्रक्रिया निर्धारित करेगी।

विश्वविद्यालयों को ज्ञान और अनुसंधान पर अधिक ध्यान देना चाहिए - केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी

'एसएनडीटी' विश्वविद्यालय का 75वां दीक्षांत समारोह

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। यदि हमारे ज्ञान का उपयोग समाज के लिए किया जाए, तो उसका महत्व बढ़ जाता है। ऐसे में, ऐसी शिक्षा प्रदान करना समय की मांग है जो लोगों के दैनिक जीवन को आसान बनाए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि विश्वविद्यालयों को ज्ञान और नए अनुसंधान पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे महिला विश्वविद्यालय (एसएनडीटी) के 75वें दीक्षांत समारोह में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांतदादा पाटिल, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. उज्ज्वला चक्रदेव, प्राध्यापक और छात्र उपस्थित थे।

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि छात्रों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जो उन्हें एक अच्छा व्यक्ति और जीवन में सफल बनाए। भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नए अनुसंधान किए जाने चाहिए। जिन

क्षेत्रों में हम आयात पर निर्भर हैं, हमें भविष्य में नए शोध करके उन क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि 'एसएनडीटी' विश्वविद्यालय ने महिलाओं के लिए शिक्षा के विविध द्वार खोले हैं। पुण्यश्लोकी अहिल्या देवी होल्कर ने अनेक कठिनाइयों को पार करके लोगों के न्याय के लिए कार्य किया, हमें उनके आदर्श को सामने रखकर कार्य करना चाहिए। मुझे गर्व है कि उनके इस कार्य को सम्मानित किया जा रहा है। यह कहते हुए उन्होंने महर्षि कर्वे के सामाजिक कार्यों का भी स्मरण कराया।

पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को सार्वजनिक जीवन और महिला सशक्तिकरण में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर (डी. लिट.) की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। साथ ही, दीक्षांत समारोह के दौरान स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा के छात्रों को उपाधियाँ प्रदान की गईं और शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में योगदान देने वाले डॉक्टरेट उपाधि धारकों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

इस वर्ष, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय को एनएएसी से 'ए' ग्रेड प्राप्त हुआ है और विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण, अनुसंधान, सुशासन और छात्राओं की समग्र प्रगति के लिए कई शैक्षिक पहल की गई हैं, यह जानकारी विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. उज्ज्वला चक्रदेव ने अपने परिचयात्मक भाषण में दी।

राष्ट्रव्यापी साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान 25 सितंबर से शुरू

नागरिकों के लिए एक महीने तक चलने वाला राष्ट्रव्यापी साइबर सुरक्षा और गोपनीयता जागरूकता अभियान

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने और सभी के लिए सुरक्षित साइबर लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद ने 25 सितंबर 2025 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में 'रिंग द बेल फॉर सिक्योरिटी' नामक एक अभियान का आयोजन किया है। यह अभियान राष्ट्रव्यापी साइबर सुरक्षा जागरूकता माह (सीएसएएम) 2025 के रूप में चलाया जाएगा।

इस अभियान का उद्घाटन सूचना प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के निवेश सलाहकार कौस्तुभ धावसे, सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय के प्रमुख सचिव एवं महानिदेशक बृजेश सिंह, साथ ही गृह मंत्रालय, सीईआरटी-इन, सेबी और बीएसई के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।

यह अभियान गृह मंत्रालय के भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र (घ4ण), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऍंऊ-घ्ह के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है और उद्योग

जगत के सहयोगी संगठनों ने भी इसमें योगदान दिया है। यह अभियान नागरिकों, संगठनों और हितधारकों को अच्छी साइबर सुरक्षा आदतें अपनाने, साइबर सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, और नागरिकों को बढ़ते साइबर अपराधों के बारे में शिक्षित करेगा तथा ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

नासिक सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए वन विभाग का आरक्षण रद्द किया जाए- मंत्री छगन भुजबल

मुंबई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने निर्देश दिया है कि महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से सटी उपलब्ध भूमि पर एक सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाया जाएगा और इस भूमि पर वन विभाग का आरक्षण रद्द करने के लिए शीघ्रता से कार्य किया जाए।

नासिक में सरकारी मेडिकल कॉलेज के संबंध में मंत्रालय में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वन मंत्री गणेश नाइक, वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त अनिल भंडारी, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. राजेंद्र बंगाल आदि उपस्थित थे।

मंत्री श्री भुजबल ने कहा कि सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेज और उससे जुड़े अस्पताल के लिए स्वीकृति दे दी है। कॉलेज का निर्माण स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से सटी उक्त भूमि पर किया जाएगा और इसके लिए सरकार द्वारा अतिरिक्त भूमि भी उपलब्ध कराई गई है। भुजबल ने कहा कि विश्वविद्यालय और चिकित्सा शिक्षा विभाग को इस संबंध में समन्वित कार्रवाई करनी चाहिए।

वन मंत्री श्री नाइक ने कहा कि जनहित में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। संबंधित सरकारी एजेंसियों को उक्त भूमि पर वन विभाग के आरक्षण को रद्द करने के लिए तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। प्रस्ताव प्राप्त होते ही वन विभाग कार्रवाई करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शक निर्णय के अनुसार, वन विभाग ऐसी भूमि के नियमितीकरण की प्रक्रिया करता है।

कोल्हापुर में शुरू हुई 'स्मार्ट पार्किंग' व्यवस्था से यातायात प्रबंधन को नई दिशा- पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई

नवरात्रि उत्सव के दौरान पर्यटकों के लिए सुगम और सुसज्जित सुविधाएँ

मुंबई।महाराष्ट्र के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र कोल्हापुर में, विशेष रूप से नवरात्रि उत्सव के दौरान, श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन विभाग ने अत्याधुनिक 'स्मार्ट पार्किंग' व्यवस्था लागू की है। पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी पहल से यातायात की भीड़ कम होगी, जिससे पर्यटकों को एक सुगम और सुखद अनुभव प्राप्त होगा। कोल्हापुर महाराष्ट्र का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव है। स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था पर्यटकों के अनुभव को समृद्ध करेगी, पर्यावरण की रक्षा करेगी और यातायात प्रबंधन को एक नई दिशा देगी। इस पहल को राज्य के अन्य पर्यटन स्थलों पर भी लागू करने की योजना है। इस प्रणाली का उद्देश्य शहर के मध्य क्षेत्र में पार्किंग स्थल आसानी से उपलब्ध कराना और यातायात व्यवस्था की योजना को और अधिक लचीला बनाना है। पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई ने बताया कि इस मोबाइल ऐप-आधारित प्रणाली से पर्यटक और स्थानीय नागरिक अपनी सुविधानुसार पार्किंग स्थल ढूंढ और बुक कर सकेंगे।

पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई ने बताया कि इस परियोजना को पर्यटन विभाग, कोल्हापुर जिला कलेक्ट्रेट और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है। उम्मीद है कि इससे कोल्हापुर का सांस्कृतिक और पर्यटन अनुभव और भी सुखद और सुविधाजनक बनेगा।

ऑनलाइन बुकिंगः पर्यटक मोबाइल ऐप या दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से पहले से पार्किंग स्थल बुक कर सकेंगे। रीयल-टाइम अपडेटः उपलब्ध पार्किंग स्थलों की जानकारी रीयल-टाइम में अपडेट की जाएगी। यातायात की भीड़भाड़ में कमीः इस प्रणाली से यातायात की भीड़भाड़ कम होगी क्योंकि वाहन चालकों को पार्किंग स्थल खोजने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा।

सम्पादकीय

जीएसटी से उपभोक्ताओं, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों को राहत मिलने की उम्मीद

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सुधार सोमवार से लागू हो गए। इसके बाद कई आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर दरों में कटौती से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इससे स्थानीय विनिर्माण आधार को भी मजबूती मिलेगी तथा बचत, निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसमें दोराय नहीं कि वर्ष 2017 में शुरू हुए जीएसटी के सफर में सुधारों का यह महत्त्वपूर्ण पड़ाव है। इससे न केवल उपभोक्ताओं, बल्कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों को भी राहत मिलने की बात की जा रही है।

मगर, सवाल यह है कि क्या करों में कटौती का सीधा और तत्काल लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंच पाएगा? हालांकि, सरकार का दावा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए माकूल व्यवस्था की जा रही है, लेकिन यह भी सच है कि करों में कटौती के प्रभाव को लेकर आम उपभोक्ताओं के पिछले अनुभव संतोषजनक नहीं रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि मौजूदा कर सुधार उम्मीदों की कसौटी पर कितने खरे उतर पाते हैं।

जीएसटी सुधारों की एक खास बात यह है कि अब इसमें मुख्य रूप से पांच फीसद और अठारह फीसद की सिर्फ दो श्रेणियां रखी गई हैं। इसके तहत कई आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर की दर घटाकर पांच फीसद या शून्य कर दी गई है। जीवन रक्षक दवाएं, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा अब कर-मुक्त हो गए हैं। खेती-किसानी के लिए जरूरी कृषि उपकरणों पर कर दरों को भी तर्कसंगत बनाया गया है।

सरकार का मानना है कि जीएसटी की दरों में कमी से किराने और रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के खर्च में करीब तेरह फीसद की बचत होगी, जबकि शिक्षा से जुड़ी सामग्री, कपड़े, जूते और दवाइयों की खरीद पर 7-12 फीसद की बचत का अनुमान है। कम कर, कम कीमतें और सरल नियमों का मतलब है बेहतर बिक्री, कम अनुपालन बोझ और अवसरों में वृद्धि होगी। इससे छोटे उद्योगों, व्यापारियों और दुकानदारों को भी कारोबार में आसानी होने की उम्मीद है।

चूंकि, ये कर सुधार त्योहारों की शुरूआत पर नवरात्रि के पहले दिन लागू हुए हैं, इसलिए सरकार की ओर से इन्हें 'जीएसटी बचत उत्सव' के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। मगर उपभोक्ता के लिए असली उत्सव तब होगा, जब वास्तव में उन्हें कर छूट का सीधा लाभ मिलेगा। एक बड़ी समस्या यह भी है कि जिन कंपनियों के पास पहले से तैयार सामान का भंडार है, क्या वे उस पर दाम कम करेंगी। हालांकि, सरकार की ओर से इसके लिए दिशा-निर्देश बनाए गए हैं, लेकिन आम उपभोक्ताओं का एक वर्ग अब भी भ्रम की स्थिति में है। जीएसटी दरों में कटौती का एक मकसद भारत पर अमेरिका की ओर से लगाए गए पचास फीसद शुल्क के प्रभाव को कम करना भी है। आर्थिक विशेषज्ञ भी इस बात से सहमत हैं कि करों में कमी से लोगों की बचत में इजाफा होगा और उनकी खरीद क्षमता बढ़ेगी, जिसके परिणामस्वरूप देश में वस्तुओं की खपत भी बढ़ेगी। करों में राहत के साथ-साथ स्वदेशी उत्पादों को तरजीह देने और देश में उनकी खपत को बढ़ाने का मसला भी अहम है। बाजार में विदेशी सामान की चमक-दमक उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। सरकार की ओर से उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन इन्हें व्यापक बनाने की जरूरत है। तभी आयात पर निर्भरता कम होकर आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो पाएगा।

भारत में गरीबी और अशिक्षा का आंकड़ा डिजिटल निरक्षरता का एक बड़ा कारण

पांच ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य से रह गए हम काफी दूर

विमुद्रीकरण के बाद से ही भारत सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। इस क्रम में डिजिटल इंडिया और ई-शासन जैसे अभियान में तेजी लाई गई। वर्ष 2024-25 तक पांच ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि यह आंकड़ा मौजूदा समय में मुश्किल से चार ट्रिलियन डालर के इर्द-गिर्द है। भारत डिजिटल सेवा क्षेत्र में बढ़ रहे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक आदर्श गंतव्य माना जाता रहा है। गौरतलब है कि यहां कुछ क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर विशिष्ट सीमाएं और प्रतिबंध हैं। उदाहरण के लिए विनिर्माण और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सौ फीसद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। जबकि डिजिटल क्षेत्र में छब्बीस फीसद तक एफडीआइ की अनुमति है, जो उच्च मांग के कारण तेजी से बढ़ रहा है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय आय में 11.74 फीसद का योगदान दिया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ), क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रगति से वर्ष 2024-25 तक यह योगदान बढ़ कर 13.42 फीसद हो जाने का अनुमान है। डिजिटलीकरण के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है और 2030 तक, डिजिटल अर्थव्यवस्था द्वारा कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग पांचवें हिस्से के योगदान का अनुमान है।

इसकी सबसे बड़ी वजह जनसंख्या है, जिसमें नवउद्यम की भरपूर संभावनाएं हैं। पिछले कुछ वर्षों में निजी और सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप प्रदान किया गया। मगर भारत में गरीबी और अशिक्षा का आंकड़ा डिजिटल निरक्षरता का एक बड़ा कारण है। गौरतलब है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हर पांचवां व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है, जबकि हर चौथा नागरिक अशिक्षित है। किसी के पास मोबाइल होना डिजिटल होने का प्रमाण नहीं है, जब तक कि उसके

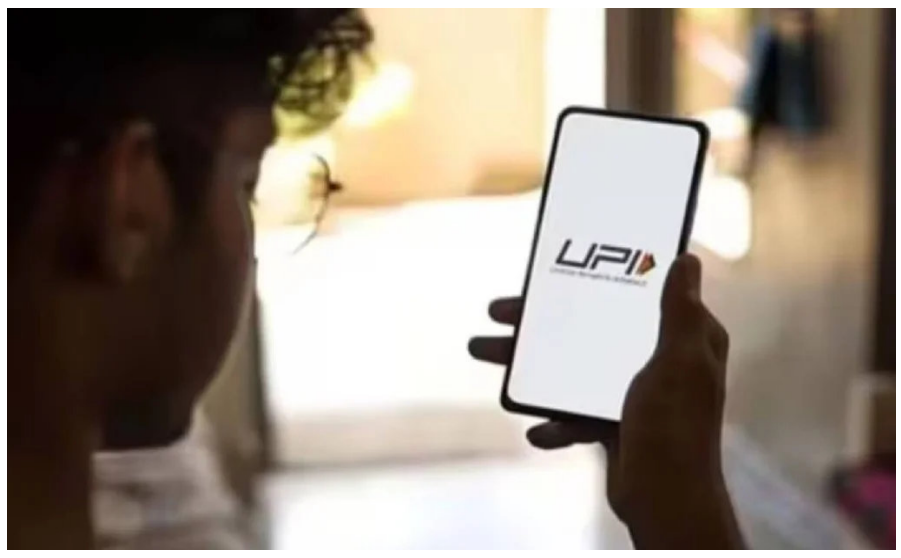

पास इंटरनेट संपर्क आदि की सुविधा और जानकारी न हो।

एसोचैम की एक रपट से पता चलता है कि नीतियों में अस्पष्टता और ढांचागत कठिनाइयों के कारण महत्त्वाकांक्षी डिजिटल परियोजना के सफल कार्यान्वयन में अनेक चुनौतियां हैं, जिनमें बार-बार नेटवर्क संपर्क का टूट जाना भी है। 'कनेक्ट इंडिया' मिशन के तहत राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति- 2018 ने एक मजबूत डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे के निर्माण के उद्देश्य से वर्ष 2022 तक एक करोड़ सार्वजनिक 'वाई-फाई हाटस्पाट' लगाए जाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके अलावा, 'भारत 6जी विजन' के तहत वर्ष 2022 तक एक करोड़ और 2030 तक पांच करोड़ सार्वजनिक 'वाई-फाई हाटस्पाट' बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। हालांकि, वर्तमान में 'पीएम-वाणी हाटस्पाट' का आंकड़ा 'भारत 6जी विजन' दस्तावेज में परिकल्पित लक्षित आंकड़े से बहुत पीछे है।

भारत का मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी कानून साइबर अपराधों को रोकने के लिहाज से बहुत प्रभावी नहीं। एटीएम कार्ड की क्लोनिंग और बैंक खाते में सेंध आदि की शिकायतें बढ़ गई हैं। बरसों पहले कहा गया था कि भारत में जैसे-जैसे डिजिटलीकरण बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे विशेषज्ञों की संख्या भी बढ़ानी होगी। हालांकि राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन की शुरूआत वर्ष 2020 तक भारत के प्रत्येक घर में कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए गई थी। देश में लगभग अड़तीस फीसद परिवार डिजिटल साक्षर हैं। हालांकि, केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता दर में काफी भिन्नता है, शहरी क्षेत्रों में यह दर इकसठ फीसद, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह पच्चीस फीसद है।

गौरतलब है कि दस वर्ष पहले भारत ने डिजिटल इंडिया मिशन की शुरूआत की थी, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना था। वर्ष 2014 में टेलीफोन कनेक्शन 93.3 करोड़ से बढ़ कर 2025 में 120 करोड़ से अधिक हो गए। जहां पहले संचार-घनत्व 75.23 फीसद था, वहीं 2024 तक यह बढ़ कर 84.49 फीसद हो गया। शहरी कनेक्शन 55.5 करोड़ से बढ़ कर 66 करोड़ दस लाख हो गए। जबकि ग्रामीण कनेक्शन 37.7 करोड़ से बढ़ कर 52.7 करोड़ हो गए। इतना ही नहीं मोबाइल ग्राहकों की संख्या 116 करोड़ तक पहुंच गई। इंटरनेट कनेक्शन 96.96 करोड़ हो गए हैं, जो पिछले दस वर्ष की तुलना में बहुत बड़ी वृद्धि है। जब देश में ई-शासन की बात होती है, तो नए प्रारूप और एकल खिड़की संस्कृति मुखर हो जाती है। नागरिक केंद्रित व्यवस्था के लिए सुशासन की लंबे समय से दरकार रही है। ऐसे में ई-शासन इसका बड़ा आधार है।

ई-शासन की रूपरेखा पांच दशक पुरानी है। हालांकि उस दौर में शासन डिजिटल तो नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रानिक विधा के अंतर्गत आधारभूत व्यवस्था को सुसज्जित करने का प्रयास हो रहा था। गौरतलब है कि इलेक्ट्रानिक विभाग की स्थापना 1970 में हुई थी। जबकि 1977 में राष्ट्रीय सूचना केंद्र के साथ ई-शासन की दिशा में कदम उठाया गया था। ई-शासन को बढ़ावा देने की दिशा में 1987 में शुरू हुआ राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क क्रांतिकारी कदम था, जिसका मुखर रूप 1991 के उदारीकरण के बाद सामने आया। वर्ष 2006 में राष्ट्रीय ई-शासन योजना लाए जाने के बाद ई-शासन व्यापक रूप में सामने आया और इसी कड़ी में एक जनवरी 2015 को डिजिटल इंडिया की अवधारणा को जमीन पर उतार कर आमजन के जीवन को सूचना तकनीक के माध्यम से बेहतर बनाने का जो प्रयास किया गया, उससे देश डिजिटलीकरण की ओर तेजी से बढ़ा।

डिजिटल शासन के तीन मुख्य क्षेत्रों में प्रत्येक नागरिकों की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचा, शासन और मांग आधारित सेवाएं तथा नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण शामिल है। ई-शासन से सरकारी कार्यों में दक्षता बढ़ती है, जबकि एक स्तंभ के रूप में इसमें लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन शुमार होते हैं। गौरतलब है कि डिजिटल इंडिया भारत को सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसमें जनता और सरकार के बीच संवाद को मजबूती मिलने के साथ ही व्यवसाय और नए अवसरों का सृजन भी शामिल था। सुशासन लोक सशक्तीकरण का पर्याय है जबकि सरकारी योजनाएं लगभग आठ दशक से ऐसे ही सशक्तीकरण की खोज में है। ई-शासन इस दिशा में एक ऐसा उपकरण है जो योजनाओं को पारदर्शी तरीके से जनता तक परोसता है।

भ्रष्टाचार और पारदर्शिता एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। ई-शासन पारदर्शिता का एक अच्छा माध्यम है। बावजूद इसके भारत में डिजिटल शासन के सामने कई चुनौतियां हैं। गौरतलब है कि ई-शासन के लिए किए जाने वाले उपाय महंगे हैं और इनकी अवसंरचना में बिजली, इंटरनेट, डिजिटल उपकरण आदि बुनियादी सुविधाओं का यदि अभाव बना रहता है, तो चुनौतियां बरकरार रहेंगी। सरकार के सभी कार्यों में प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग ई-गवर्नेंस कहलाता है। किसानों के खाते में सम्मान निधि का हस्तांतरण डिजिटल शासन का ही उदाहरण है। ई-लर्निंग, ई-बैंकिंग, ई-टिकटिंग और ई-सुविधा आदि शासन को सुशासन की ओर ले जाते हैं। देश में करीब साढ़े छह लाख गांव और ढाई लाख पंचायतें हैं, जहां बिजली और इंटरनेट संपर्क एक आम समस्या है। सवाल यह है कि शहर हो या गांव, ई-शासन की सभी को आवश्यकता है और यह इंटरनेट पर निर्भर है।

उपवास और विश्वास की शक्ति, इस अनमोल खजाने की सुरक्षा बहुत ही ध्यानपूर्वक जरूरी

विश्वास हमारे सामाजिक पारिवारिक जीवन का आधार है। या यों कहें कि जीवन का आधार स्तंभ और एक अमूल्य पूंजी है। इसका रुपए-पैसे से मोल नहीं लगाया जा सकता है और न ही किसी का विश्वास मूल्य चुकाकर प्राप्त किया जा सकता है। इसे तो बस प्रेम, करुणा, संवेदना, निश्छल हृदय द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसे हम भले ही देख नहीं सकते हैं, लेकिन जीवन के हर क्षण में महसूस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हम सब कहीं न कहीं किसी न किसी पर विश्वास करते हैं। हमारे सभी संबंध विश्वास पर ही टिके होते हैं। विश्वास नहीं होने पर रिश्ते कांच की तरह टूट कर बिखर जाते हैं।

चाहे वह दांपत्य, मित्रता या रक्त संबंध हो, ये सभी रिश्ते विश्वास की भूमि पर ही उपजते, सींचे जाते, संवरते, हंसते-मुस्कुराते हैं। बिना विश्वास के किसी भी रिश्ते की आयु लंबी नहीं होती है। रिश्ते में अगर विश्वास न हो, तो उनमें कोई रस नहीं रहेगा। फिर रिश्ता खाली ठूंठ के समान रह जाएगा और सिर्फ मन के दुख का कारण बनेगा। ईश्वर को हम कभी देखते नहीं हैं, लेकिन यह विश्वास होता है कि वह हर जगह उपस्थित है और विपत्ति में हमारी सहायता करता है। यह विश्वास ही हमें बड़े से बड़ा कार्य करने का साहस और बल प्रदान करता है।

उदाहरण के लिए, सामान्य दिनों में हम एक दिन भोजन नहीं करते हैं, तो हमें कमजोरी, चक्कर आदि से दिक्कत महसूस होने लगती है, लेकिन किसी पूजा-आराधना के दौरान उपवास भक्ति, विश्वास और श्रद्धा से सहजता पूर्वक रख लेते हैं। यह मात्र विश्वास की ही शक्ति है कि हम अपनी भूख जैसी प्राकृतिक इच्छा को भी नियंत्रित कर लेते हैं। ऐसे में यह सोचा जा सकता है कि विश्वास के बल पर क्या कुछ नियंत्रित करना संभव नहीं होगा। एक पिता जब अपने बच्चे को खेलने के लिए हवा में उछालता है तो बच्चा हंसता रहता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसके पिता उसे गिरने नहीं देंगे। उसका विश्वास उसके चेहरे पर मुस्कान बनकर झलकता है। विश्वास ही वह शक्ति है, जिससे बच्चा बिना भयभीत हुए हंसता रहता है। अगर बच्चे को उसके पिता के स्थान पर कोई और हवा में उछाल दे तो वह भयभीत होकर सहम जाएगा। मगर पिता के ऊपर उसका विश्वास उसके डर के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेता है।

विश्वास इतना शक्तिशाली होता है कि इंसान उसके भरोसे ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई भी पूरी कर लेता है। विश्वास न रहे तो कमजोर इतना हो जाता है कि थोड़ी-सी चूक में बिखर कर रह जाता है। विश्वास हमारे मन का रचा खेल और उसकी बनाई दुनिया होती है, लेकिन इसकी शक्तियां अद्भुत हैं। कई बार लोग यह मानते हैं कि विश्वास का संबंध बुद्धि से है, मगर विश्वास का संबंध बुद्धि, विवेक और भरोसा सबसे है। इसका सीधा संबंध हृदय से भी होता है। बड़े लोगों के बारे में तो यह कहा या सकता है कि वे बुद्धि से काम लेते हैं, लेकिन जब अबोध बालकों की बात आती है तो यह बात तर्कहीन हो जाती है कि विश्वास सिर्फ बुद्धि से संबंधित है। विश्वास गहरे भरोसे से भी संबंधित है।

दरअसल, विश्वास मन की एक स्थिति है, जिसमें मन यह मान लेता है कि 'ये ऐसा है'। यह मात्र हमारा मानना होता है, न कि जानना होता है। और यह मानना एकतरफा होता है। जरूरी नहीं है कि दूसरी तरफ भी मनोनुकूल स्थिति हो। और जब स्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती है तो हमें बुरा लगता है। यह मात्र हमारी रची गई दुनिया होती है, जिसमें दूसरा व्यक्ति हमारी इच्छा के अनुसार किरदार नहीं निभाता है और तब हमारे विश्वास को ठेस लगती है। हमारी अपेक्षाएं कुछ और होती हैं।

विश्वास टूटने पर भावनात्मक आघात, धोखे का एहसास, संबंध में दरार और हृदय को बेहद पीड़ा होती है, क्योंकि हमें भावनात्मक और मानसिक आघात पहुंचता है। इसलिए हम धोखा महसूस करते हैं। कभी-कभी तो आत्मविश्वास भी डगमगा जाता है। अब चूंकि विश्वास की दुनिया हमने खुद रची होती है तो जब यह टूटता है तो यह मन को ही नहीं, जीवन की दिशा और दृष्टि को भी प्रभावित करता है। विश्वास और भरोसे की प्रवृत्ति भी ऐसी होती है कि एक बार टूटने के बाद इसे फिर से पहले जैसा मूल स्वरूप में बनाना संभव नहीं होता है। फिर भी प्रतिदिन लाखों लोगों के विश्वास टूटते और बनते-बिखरते रहते हैं।

सबसे पहले तो हमें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए किसी का विश्वास नहीं टूटने पाए। यह बहुत अनमोल खजाना है तो इसकी सुरक्षा बहुत ही ध्यानपूर्वक करनी चाहिए। कोई हमारे ऊपर अपना विश्वास समर्पित कर रहा है, तो हम अपने आपको सौभाग्यशाली मानें कि हमें कोई व्यक्ति इसका पात्र समझ रहा है। तब हमारा भी कर्तव्य बन जाता है कि हम उस लायक बन कर उसके भरोसे को सही साबित करें, लेकिन अगर कोई विश्वास तोड़ ही दे तो हमें अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। बल्कि इसे एक अनुभव और सीख के तौर पर लेना चाहिए, ताकि आगे से जीवन में अगर हम किसी के ऊपर निश्छल विश्वास करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर करें जो सचमुच में विश्वास करने का पात्र हो।

विदेशी निर्भरता घटाइए, राष्ट्रीय सफलता बढ़ेगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत दिनों गुजरात के भावनगर में कहा है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन अन्य देशों पर निर्भरता है और जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता होगी, उतनी ज्यादा राष्ट्रीय विफलता बढ़ेगी। उन्होंने यहां तक कहा कि 140 करोड़ भारतीयों का भविष्य बाहरी ताकतों पर नहीं छोड़ा जा सकता और इसके लिए भारत को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। आत्मनिर्भरता देश के सभी समस्याओं का समाधान है और यही राष्ट्रीय सौभाग्य और विकास की कुंजी है।

इससे साफ है कि 2025 की अंतिम तिमाही से पहले चले अंतरराष्ट्रीय दांवपेचों के दृष्टिगत प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को आगाह कर दिया है कि जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता होगी, उतनी ज्यादा राष्ट्रीय विफलता होगी। ऐसा कहकर उन्होंने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है। एक तरफ तो उन्होंने चीन से आयात पर और अमेरिका को निर्यात पर या ऐसे ही अन्य देशों पर निर्भरता समाप्त करने के लिए सोच और साधन दोनों बदलने का आह्वान किया है।

वहीं, दूसरी तरह विदेशी बहु समझी जाने वाली कांग्रेस नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी और उनके पुत्र-पुत्रियों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के विदेशी तिकड़मों से भी सावधान रहने के इशारे किए हैं, क्योंकिः उनका मुस्लिम प्रेम, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका प्रेम और राष्ट्रविरोधी ताकतों को सियासी संरक्षण देश के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। चूंकि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और सोनिया गांधी-प्रियंका गांधी क्रमशः राज्यसभा व लोकसभा के सांसद हैं। इसलिए इनकी हर कोशिशों पर देश-दुनिया की नजर रहती है।

प्रधानमंत्री मोदी की मानें तो किसी भी मामले में विदेशी निर्भरता से राष्ट्रीय स्वाभिमान को नुकसान पहुंचता है। जब देश अपनी जरूरतों के लिए बाहरी देशों पर निर्भर होता है, तो उसका स्वाभिमान कमजोर पड़ता है। देश का विकास और फैसले बाहरी ताकतों के प्रभाव में आ जाते हैं, जो राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हो सकते हैं। वहीं विदेशी निर्भरता से आर्थिक नुकसान और अस्थिरता पैदा होती है। विदेशी निर्भरता से देश की आर्थिक सुरक्षा कमजोर होती है। वैश्विक बाजारों या विदेशी साधनों पर निर्भरता से आर्थिक संकट आने पर देश प्रभावित होता है, जिससे विकास रुक सकता है।

विदेशी निर्भरता से विकास भी बाधित होता है। आत्मनिर्भरता की कमी के कारण देश अपने संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं कर पाता और उद्योग, तकनीक, और नौकरियों का विकास रुक जाता है। इससे राष्ट्रीय विकास की गति धीमी हो जाती है। इसके अलावा, विदेशी निर्भरता से रणनीतिक खतरा भी बढ़ता है। सुरक्षा और महत्वपूर्ण संसाधनों में विदेशी निर्भरता से राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर होती है। आपातकाल में या भू-राजनीतिक तनाव में यह बड़ी समस्या बन सकती है।

यही वजह है कि भारत अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कई तरीकों और नीतियों पर काम कर रहा है। एक ओर भारत स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा दे रहा है, जिसके तहत घरेलू उत्पादन पर जोर देने से जहां आयात कम होगा, वहीं देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसके लिए 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना जरूरी है। वहीं, दूसरी ओर भारत स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। इसके तहत नई तकनीकों और नवाचार को अपनाकर भारत को तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम तेज की जा रही है, जिससे रोजगार निर्माण और आर्थिक विकास भी होगा।

वहीं, सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी मजबूत करने पर फोकस कर रही है। इससे अनुसंधान-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश से भारत अपनी तकनीकी निर्भरता घटा रहा है। वहीं कौशल विकास के द्वारा युवाओं को कौशल शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के साथ-साथ उद्यमिता के लिए तैयार करने की कोशिशें जारी हैं। वहीं, कृषि और ग्रामोद्योगों का सशक्तिकरण किया जा रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ाने, उर्वरकों और कृषि उपकरणों का स्थानीय उत्पादन बढ़ाने की पहल जारी है।

इसके अलावा डिजिटल स्वाधीनता के तहत स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीकों के विकास एवं उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं, ऊर्जा स्वतंत्रता के तहत नवीनीकरणीय ऊर्जा, जैसे- सौर, पवन, और हाइड्रोजन ऊर्जा पर निवेश कर ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने की मुहिम जारी है। वहीं, सरकारी योजनाओं के तहत

पीएम स्वनिधि योजना, जैसे- छोटे व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस अभियान को 2020 में शुरू किया था और इसे 2047 तक एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य से जोड़ा गया है। इसके तहत रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, और कृषि जैसे सभी प्रमुख क्षेत्र आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रहे हैं। इस प्रकार भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए व्यापक आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और नीति स्तर पर काम करना होगा जो देश की समग्र ताकत और स्थिरता को बढ़ाएगा।

जहां तक विदेशी निर्भरता कम करने के मुख्य उपाय की बात है तो रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की कोशिशें तेज हैं। इसके तहत रक्षा उपकरणों, हथियारों और तकनीकी संसाधनों का अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादन करने की पहल तेज है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की है, जिसमें 3, 000 से अधिक वस्तुओं का घरेलू उत्पादन सुनिश्चित किया गया है। इससे विदेशों से रक्षा उपकरणों की निर्भरता कम होती है और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होती है।

वहीं, स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके दृष्टिगत 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत घरेलू उद्योगों और एमएसएमइज (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) को समर्थन देने को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि आयात की जगह घरेलू उत्पादन बढ़े। वहीं, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके मद्देनजर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), निजी कंपनियों, स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों के बीच सहयोग बढ़ाकर तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल करने की मुहिम तेज की गई है।

वहीं, औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण करते हुए रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना, निवेश और प्रोत्साहन से स्वदेशी उत्पादन को तेजी देने की पहल परवान चढ़ाई जा चुकी है। वहीं, निर्यात और व्यापार सुधार के तहत बंदरगाहों और व्यापार प्रक्रियाओं को सरल और सक्षम बनाने की मुहिम तेज है, ताकि विदेशी निर्भरता कम होकर स्वदेशी व्यापार बढ़े। वहीं, विदेशी निर्भरता घटाने के लिए ऊर्जा, कृषि, और डिजिटल क्षेत्र में स्थानीय समाधानों को अपनाने और विकसित करने पर बल दिया जा रहा है। इसके लिए उन सरकारी नीतियों और योजनाओं को लागू किया जा रहा है जो विदेशी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करें। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि चिप्स (सेमीकंडक्टर चिप्स) व जहाज जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भारत में ही विकसित करने होंगे ताकि विदेशी निर्भरता समाप्त हो। आत्मनिर्भरता ही देश के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूत नींव है। इस प्रकार, स्वदेशीकरण, स्थानीय उत्पादन, अनुसंधान विकास, और नीति स्तर पर सुधार करके भारत अपनी विदेशी निर्भरता कम कर सकता है। यही वजह है कि भारत में स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के कई प्रभावी उपाय हैं जो सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्तर पर अपनाए जा सकते हैं। स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और बढ़ावा देने के दृष्टिगत लोगों को जागरूक करना है ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करें। इससे घरेलू उद्योगों को समर्थन मिलेगा। वहीं, सरकार के समर्थन और प्रोत्साहन से सरकार को स्वदेशी उत्पादकों को अनुदान, सहूलियत भरे ऋण, टैक्स छूट जैसे वित्तीय प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वे उत्पादन बढ़ा सकें। साथ ही सरकार द्वारा प्रचार-प्रसार अभियान चलाकर स्वदेशी वस्तुओं की महत्ता और गुणवत्ता जनता तक पहुंचाई जाए।

वहीं, गुणवत्ता में सुधार और नए डिज़ाइन से स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता और पैकेजिंग बेहतर करनी होगी ताकि वे बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बने रहें। इस हेतु उत्पादों के नए डिज़ाइनों और तकनीकों को अपनाना आवश्यक है। वहीं, स्थानीय मेलों, प्रदर्शनियों और सोशल मीडिया प्रचार के माध्यम से स्वदेशी उत्पादों के प्रचार के लिए स्थानीय स्तर पर मेले, हाट और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार सोशल मीडिया व अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इनके प्रचार-प्रसार से युवाओं व व्यापक जनता को जोड़ा जा सकता है।

कौशल विकास और पारंपरिक उद्योगों का संवर्द्धन प्रदान करने की नीति के तहत हथकरघा, कुटीर उद्योग, जैविक खेती जैसे पारंपरिक और ग्रामीण उद्योगों में युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार दिए जा रहे हैं। इससे स्थानीय उत्पादन बढ़ेगा और सांस्कृतिक परंपराएं जीवित रहेंगी। वहीं, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को प्रेरित करने से व्यापार संगठन और नागरिक समाज मिलकर स्वदेशी उत्पादों के लिए जन-अभियान चलाएंगे। इससे दुकानों में 'केवल भारतीय सामान' जैसी पहल कर लोगों के बीच स्वदेशी की जागरूकता बढ़ाने की कोशिशें परवान चढ़ेंगी।

संरक्षणवाद और आर्थिक राष्ट्रवाद के तहत घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए उचित व्यापार नीति बनाने की पहल तेज है जिससे आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं, सरकारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर स्वदेशी उत्पादकों को प्राथमिकता देकर सरकारी खरीद में उनका हिस्सा बढ़ाया गया है जिससे संतुलित विकास को बढ़ावा मिला है। कहना न होगा कि इन उपायों से भारत में स्वदेशी उत्पादन को मजबूती मिलेगी, जो आर्थिक आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय विकास का ठोस आधार बनेगा।

परमार्थ निकेतन मां गंगा के पावन तट पर आयोजित श्रीमद्भागवत भाव कथा का समापन

स्वामी चिदानन्द सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती के पावन सान्निध्य में श्रद्धेय गोवत्स राधाकृष्ण महाराज के श्रीमुख से हो रही श्रीमद्भागवत भाव कथा का विश्राम

ऋषिकेश। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानन्द सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती के पावन सान्निध्य में श्रद्धेय गोवत्स राधाकृष्ण महाराज के श्रीमुख से परमार्थ गंगा तट पर प्रवाहित हो रहा श्रीमद् भागवत भाव कथा के प्रवाह का विश्राम हुआ। कथा आयोजक एलएन, कोटा राजस्थान से आये समस्त श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक आनन्द और मानसिक शांति का अनुभव किया। इस दिव्य अवसर पर स्वामी चिदानन्द सरस्वती ने नवरात्रि के महत्व पर गहनता से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि नवरात्रि केवल उपवास या अनुष्ठान का पर्व नहीं है, बल्कि यह शक्ति की आराधना, आत्मसंयम और दिव्यता का महोत्सव है। नौ दिन, नौ रात्रियाँ और नौ दिव्य ऊर्जा रूपों के माध्यम से नवरात्रि जीवन में रचनात्मकता, शक्ति, धैर्य और आध्यात्मिक प्रगति को आलोकित करती है।

स्वामी ने कहा कि कथा केवल शब्दों का संकलन नहीं, बल्कि जीवन को दृष्टि, दिशा और प्रकाश देने वाला साधन है। जब हम श्रीमद्भागवत, रामायण, महाभारत आदि दिव्य कथा का श्रवण करते हैं, तो हमारे हृदय, मस्तिष्क और चेतना में सूक्ष्म परिवर्तन आरंभ होता है। कथा हमारे भावों को पवित्र करती है, करुणा, सहानुभूति और समर्पण की अनुभूति जागृत करती है। यह हमें अच्छाई, सच्चाई और ऊँचाई की बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमारे विवेक और निर्णय शक्ति को भी सशक्त बनाती है।

कथा, विचारों में गहनता और स्पष्टता लाती है। कथा का प्रत्येक

चरित्र, प्रत्येक प्रसंग हमारे मन में धैर्य, साहस और आत्मसंयम की प्रेरणा देता है। कथा हमारे भाव, विचार और व्यवहार में विलक्षण परिवर्तन करती है और जब कथा गोवत्स राधाकृष्ण के मुख से भाव भक्ति से हो तो वह अपार आनंद प्रदान करती हैं। साध्वी भगवती सरस्वती ने कहा कि श्रीमद्भागवत भाव कथा केवल सुनने का अनुभव नहीं, बल्कि जीवन में धर्म, भक्ति और करुणा का अनुप्रयोग है। साध्वी ने कहा कि मां गंगा के तट पर कथा श्रवण का अनुभव अद्वितीय है। गंगा की पवित्र धारा केवल जल नहीं, बल्कि शुद्धता, शक्ति और आध्यात्मिकता का प्रवाह है। इस पावन वातावरण में कथा श्रवण करने से मन, वाणी और विचार शुद्ध होते हैं। मैने अपने जीवन में इस अनुभव के साक्षात दर्शन किये हैं। आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व जब मैं पहली बार मां गंगा के तट पर आयी थी उस समय मैने गंगा को स्पर्श किया साथ ही गंगा ने भी मुझे स्पर्श कर मेरा पूरा जीवन, भाव, चिंतन सब कुछ बदल दिया।

श्रद्धेय गोवत्स राधाकृष्ण महाराज ने श्रीमद्भागवत के मध्यम से जीवन मा अमृतपान कराया। उन्होंने कहा कि कथा श्रवण से मन में भक्ति, करुणा और संतोष का संचार होता है। कथा जीवन को नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से सशक्त बनाती है। गोवत्स ने यह भी बताया कि गंगा तट पर कथा श्रवण करने का विशेष महत्व है, क्योंकि गंगा की पवित्रता और वातावरण की दिव्यता न केवल शरीर को बल्कि हृदय और मस्तिष्क को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है।

कथा आयोजक श्रद्धेय गिरिराज एवं मित्रमंडल, तथा शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रहे एलएन ग्रुप, कोटा (राजस्थान) के गोविंद जी, राजेश जी, नवीन और विजय और पूरे परिवार ने गद्गद् हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हुये परमार्थ निकेतन से विदा ली।

जयन्त चौधरी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा की शुरुआत की

वाराणसी। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं शिक्षा राज्य मंत्री, जयन्त चौधरी ने अपनी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा की शुरुआत कई उच्चस्तरीय बैठक के साथ की, जिसका उद्देश्य कौशल और उद्यमिता के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाना है। यात्रा की शुरुआत मेलबर्न से हुई, जहाँ मंत्री जयन्त चौधरी ने ऑस्ट्रेलिया-इंडिया बिज़नेस काउंसिल के कार्यक्रम को संबोधित किया। 'स्किलिंग फॉर द फ्यूचर' विषय पर अपने विचार रखते हुए चौधरी ने प्रशिक्षण मॉडल्स को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की आवश्यकता पर बल दिया और इस बात को रेखांकित किया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर उत्तरदायी और भविष्य के लिए तैयार स्किलिंग फ्रेमवर्क का निर्माण कर सकते हैं।

इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए चौधरी ने कहा कि 'भारत और ऑस्ट्रेलिया युवाओं को भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने की साझा प्रतिबद्धता रखते हैं। यह साझेदारी न केवल युवाओं के लिए अधिक गतिशीलता और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि हमारे स्किलिंग ईकोसिस्टम विश्वभर में हो रहे औद्योगिक परिवर्तनों के अनुरूप बने रहें।'

अविका गोर ने मिलिंद चंदवानी के साथ शादी की तारीख का ऐलान किया

वाराणसी। अभिनेत्री अविका गोर अपने मंगेतर मिलिंद चंदवानी के साथ 30 सितम्बर को, नवरात्रि के शुभ दिनों में, शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। इस बहुप्रतीक्षित उत्सव का जश्न जल्द ही कलर्स के रियलिटी शो 'धमाल विद पति पत्नी और पंगा' में दिखाई देगा, जिससे उनका यह सपनों जैसा विवाह देशभर के प्रशंसकों के लिए एक यादगार पल बन जाएगा।

अविका ने कहा, 'मिलिंद और मैं बेहद खुश हैं यह बताते हुए कि हम 30 सितम्बर को, नवरात्रि के शुभ दिनों में, शादी करने जा रहे हैं। परिवार और शुभचिंतकों के आशीर्वाद और प्यार के साथ इस नए और खूबसूरत सफर की शुरुआत करना हमारे लिए अविश्वसनीय अनुभव है। आज हमने नवरात्रि के पहले दिन सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन किए और अब हम अपने शादी के निमंत्रण भेजना शुरू करेंगे - जिससे यह पल और भी खास बन गया है। मैंने हमेशा एक ऐसी शादी का सपना देखा था जिसे पूरी दुनिया मेरे साथ सेलिब्रेट करे, और मैं खुद को धन्य मानती हूँ कि यह सपना अब सच हो रहा है।' निविया बॉडी मिल्क प्रस्तुत करता है 'धमाल विद पति पत्नी और पंगा - जोड़ियों का रियलिटी चेक', जिसे को-पॉवर्ड किया है शुगर फ्री ग्रीन, कैडबरी डेयरी मिल्क, पोअर होम एयर फ्रेशनर्स, एन्वी परफ्यूम्स, लॉरियल पेरिस हायलूरॉन प्योर और अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल ने। स्पेशल पार्टनर्सः कोल्गेट और कैच मसाले। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 9:00 बजे, सिर्फ कलर्स पर।

अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 204.70 करोड़ रुपये जुटाए

वाराणसी। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अपने प्रस्तावित आईपीओ से पहले 15 एंकर निवेशकों को 27, 14, 885 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं और 754 रूपये प्रति इक्विटी शेयर (2 रूपये अंकित मूल्य वाले शेयरों पर 752 रूपये प्रीमियम सहित) के ऊपरी प्राइस बैंड पर 204.70 करोड़ रुपये जुटाए हैं। एंकर निवेशकों को आवंटित कुल 27, 14, 885 इक्विटी शेयरों में से, 15, 91, 573 इक्विटी शेयर 5 म्यूचुअल फंडों को कुल 8 योजनाओं के माध्यम से आवंटित किए गए हैं, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड और एक्सिस कैपिटल लिमिटेड इस ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।

शिक्षा और साहित्य ही वास्तविक पूँजी- सचिन वर्मा जेल अधीक्षक

सिद्धार्थनगर। जिले के जिला कारागार में ज्ञान ही व्यक्ति के चरित्र निर्माण और सकारात्मक परिवर्तन का सबसे सशक्त साधन है। इसी उद्देश्य से आजाद महाविद्यालय के प्रबंधक मुमताज अहमद ने जिला कारागार में संचालित पुस्तकालय हेतु 75 पुस्तकों का सप्रेम भेंट किया। भेंट की गई पुस्तकों में एथिक्स (नैतिक शिक्षा), विधि एवं कानून, धार्मिक साहित्य, विज्ञान, महापुरुषों की जीवनी, पर्यावरण, हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, गणित, खेलकूद (एर्द्रू) तथा अन्य विविध विषयों की पुस्तकें शामिल हैं। इन पुस्तकों के माध्यम से बंदियों को समाज, संस्कृति और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न पहलुओं से परिचित होने का अवसर मिलेगा। जिला कारागार के अधीक्षक सचिन वर्मा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि - 'पुस्तकें व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती हैं। इस प्रकार की भेंट न केवल बंदियों को ज्ञानार्जन का अवसर प्रदान करेगी, बल्कि उनमें आत्म-विश्वास एवं आत्म-सुधार की भावना को भी प्रोत्साहित करेगी।'

मुमताज अहमद ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि - 'शिक्षा और साहित्य ही वास्तविक पूँहैं। यदि

बंदी पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन करते हैं तो वे समाज में पुनः सम्मानजनक जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं।' जेल प्रशासन द्वारा यह भी अपील की गई कि विभिन्न शैक्षणिक संस्थाएँ, सामाजिक संगठन एवं एनजीओ (ञ्उध) आगे आकर पुस्तकालय को और अधिक समृद्ध बनाने में सहयोग करें, ताकि बंदियों को अध्ययन के लिए विविध विषयों की उच्चस्तरीय एवं प्रेरणादायी पुस्तकें उपलब्ध कराई जा सकें। इस अवसर पर प्रभारी जेलर मुकेश प्रकाश, शिक्षक उत्सव तिवारी, प्रभारी अभिषेक कुमार पाण्डेय मौजूद रहे।

कूड़े के ढेर से चमचमाती आदर्श गली तक - स्वच्छता ही सेवा अभियान की प्रेरक सफलता

प्रयागराज। स्वच्छ प्रयागराज, स्वस्थ प्रयागराज की दिशा में नगर निगम प्रयागराज द्वारा चलाए जा रहे 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के अंतर्गत एक और ऐतिहासिक बदलाव दर्ज हुआ है। शहर के हाशिमपुर रोड स्थित सुशीला नर्सिंग होम के बगल की बैकलाइन–जहां वर्षों से कूड़े का ढेर और गंदगी का अंबार लगा रहता था–आज एक चमचमाती, रंगीन और आदर्श गली में बदल चुकी है। नगर निगम की समर्पित टीम ने इस गली की गहन सफाई कर केवल कचरा हटाने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि स्थानीय रहवासियों, स्कूल के छात्र-छात्राओं और ण्ण कैडेट्स के साथ मिलकर घर-घर जागरूकता अभियान भी चलाया।

भित्तिचित्र एवं नव संकल्पः दीवारों पर सुंदर चित्रकारी और नवरात्रि थीम पर स्वच्छता के नव संकल्प उकेरे गए।

संदेश उकेरे गएः सार्वजनिक स्थलों की सफाई, कूड़े का संग्रहण व पृथक्करण, डस्टबिन का उपयोग और गाड़ियों में ही कचरा डालने जैसे संदेश दीवारों पर दर्ज किए गए। लगभग 500 से अधिक लोगों ने इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई।

कार्यक्रम में विशेष रूप से पार्षद आशीष कुमार द्विवेदी, कर निर्धारण अधिकारी संजय ममगाई, तथा स्वच्छता एवं खाद्य निरीक्षक अरविंद सिंह, छ्ँ टीम श्रृष्टि वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस इंदौर सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। गली की स्वच्छता और सुरक्षा को बनाए रखने हेतु स्थानीय नागरिकों का एक समूह 'स्वच्छ मोहल्ला समिति' (जिसे स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति भी कहा गया) का गठन किया गया है। यह समिति नियमित निगरानी कर सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में यहां गंदगी न फैले और गली अपनी आदर्श स्थिति में बनी रहे। जहां कभी कूड़े का अंबार लगता था, वही गली अब बच्चों के क्रिकेट खेलने का मैदान और मोहल्ले के लिए उत्सवों का स्थल बन चुकी है। यह बदलाव प्रयागराज को स्वच्छ और स्वस्थ शहर बनाने की दिशा में एक प्रेरक उदाहरण है। नगर निगम प्रयागराज सभी नागरिकों से अपील करता है कि वे अपने-अपने वार्डों और गलियों में इसी तरह की सामुदायिक भागीदारी कर 'स्वच्छता ही सेवा' को जीवन का हिस्सा बनाएं और शहर को देशभर में स्वच्छता का आदर्श प्रस्तुत करें।

मिशन शक्ति : प्रतीक्षा ने संभाला विद्यालय का प्रशासनिक कामकाज

प्रयागराज।मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत नवरात्र में बेसिक शिक्षा विभाग ने बेटियों को सशक्त बनाने की पहल किया है।इसी के अन्तर्गत मंगलवार को बालिकाओं ने प्रशासनिक कामकाज संभाला। उच्च प्राथमिक विद्यालय सुजौना जसरा प्रयागराज में कक्षा 6 की छात्रा प्रतीक्षा ने एक दिन के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक का उत्तरदायित्व निभाया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्यामाकांत द्विवेदी ने प्रतीक्षा को विद्यालयी कार्यप्रणाली और उसके क्रियान्वयन के बारे में जानकारी प्रदान किया। उन्होंने कहा शासन द्वारा यह शानदार पहल है। इससे बच्चों के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है और वह भविष्य में अच्छा करने के लिए बहुत प्रेरित होते हैं। विद्यालय की मीना मंच की नोडल शिक्षिका नाज़िया सुल्ताना ने बताया कि मिशन शक्ति महिलाओं और बालिकाओं के स्वावलंबन का प्रतीक है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देना है।इस अवसर पर विद्यालय के भारतेन्द्र त्रिपाठी, इरफ़ान अहमद, जितेन्द्र कुमार शर्मा, आशीष कुमार गुप्ता, शरद कुमार, शिशिर जायसवाल, राकेश कुमार, पूनम तिवारी, पंकज कुमार गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत यमुनानगर जोन कमिश्नरेट प्रयागराज के थाना कोरांव की एण्टीरोमियो टीम द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा व महिला सशक्तिकरण के सम्बन्ध में सार्वजनिक स्थान, स्कूल, कॉलेज इत्यादि के आस पास जागरूक करते हुए हेल्पलाइन नं-1090, 112, 1098, 1076 आदि के बारे में जानकारी दी गई।

एसआरएन हॉस्पिटल में पैर की विकृति का सफल ऑपरेशन

प्रयागराज। स्वरूप रानी नेहरू (ऐं) हॉस्पिटल के आर्थोपेडिक्स विभाग में 25 वर्षीय युवक अंकित (निवासी-चित्रकूट) का सफल ऑपरेशन किया गया। अंकित के बाएँ पैर में वाल्गस, एबडक्टेड और प्रोनेटेड प्रकार की गंभीर विकृति थी, जिससे उसे चलने-फिरने में काफी कठिनाई हो रही थी।

डॉक्टरों की टीम ने ट्रिपल आर्थ्रोडेसिस तकनीक से ऑपरेशन कर पैर की विकृति को सही किया। इस जटिल शल्यक्रिया में पैर के तीन जोड़ों को स्थायी रूप से जोड़ा गया, जिससे पैर की स्थिरता और चलने की क्षमता बहाल हो सके। ऑपरेशन का नेतृत्व असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. आनंद कुमार ने किया, जिनके साथ डॉ. सैफ और डॉ. मागध (जूनियर रेज़िडेंट) शामिल रहे। मरीज को सुरक्षित एनेस्थीसिया देने की जिम्मेदारी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अनिल सिंह और जूनियर रेज़िडेंट डॉ. सुभी ने निभाई।

इस अवसर पर एसआरएन हॉस्पिटल के प्राचार्य डॉ. वी.के. पांडेय ने कहा कि हमारे चिकित्सक लगातार जटिल से जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर रहे हैं। यह एसआरएन हॉस्पिटल की श्रेष्ठ चिकित्सा सेवाओं का प्रमाण है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए मरीज को आधुनिक तकनीक से उपचार मिलना हमारे लिए गर्व की बात है।

वहीं ऑपरेशन टीम का नेतृत्व करने वाले डॉ. आनंद कुमार ने बताया कि मरीज अंकित के पैर की विकृति गंभीर थी और उसे सुधारने के लिए ट्रिपल आर्थ्रोडेसिस ही सबसे बेहतर विकल्प था। ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा है और मरीज अब स्वास्थ्य लाभ की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे मरीजों को समय पर सही उपचार देकर उनका जीवन आसान बनाया जा सके।

हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन को चल वैजयंती पुरस्कार

प्रयागराज। केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन (कोर), प्रयागराज को हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय-1), इलाहाबाद द्वारा चल वैजयंती के तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोर कार्यालय की ओर से डॉ. संजय सिंह नेगी, मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने आयकर कार्यालय में आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में यह पुरस्कार ग्रहण किया।

पांच दिन तक रोजाना 6 घंटे बिजली आपूर्ति बाधित

थरवई। गोडवा विद्युत सब स्टेशन से सोराम-थरवई 33 हजार लाइन के जर्जर तारों को बदलने एवं मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। इस कारण क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। यह कटौती लगातार पांच दिनों तक प्रतिदिन की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपखंड अधिकारी प्रांजल मिश्रा ने बताया कि कार्य पूरा होने के बाद उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति

अखिलेश यादव के सवाल का मंत्री नन्दी ने दिया करारा जवाब

प्रयागराज। जो लोग जनता से बार-बार नकारे जा रहे हैं! फेसबुक पर सस्ते मुशायरे बघारे जा रहे हैं! अखिलेश याद है कि भूल गये? आपके कार्यकाल में माफियाओं ने उत्तर प्रदेश के विकास और तरक्की की नसबन्दी कर दी थी! आपके मुंह से नोटबन्दी शब्द वैसे ही लगता है जैसे ओसामा बिन लादेन विश्वशान्ति की बात कर रहा हो! सवाल जरूर बेतुके होते हैं जिनके बेतुके जवाब देकर ही आपको उत्तर प्रदेश के पप्पू के रूप में ख्याति मिल रही है! मेरी तो आपको भी सलाह है कि बेतुके जवाबों और बयानों से बचिये! कम से कम पूर्व मुख्यमंत्री के पद की गरिमा, गम्भीरता और मर्यादा तो बनी रहेगी!

कोई भी वीडियो पूरा देखे और सुने बिना प्रतिक्रिया देना अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है! सोशल मीडिया पर खोखली राजनैतिक कुश्ती लड़कर आप अपने अन्ध समर्थकों को जरूर बरगला सकते हैं लेकिन प्रदेश की समझदार जनता को नहीं! उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है कि 'विरासत में गद्दी तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं!'

बाकी पहले किसी अच्छे ट्यूटर से 'जीएसटी' के बारे में ट्यूशन लीजिये! आपको जीएसटी सही ढंग से लिखना तो सिखा ही देगा!

ताला तोड़कर लाखों की चोरी, गृहस्वामी घायल

थरवई। थाना क्षेत्र के भिदीऊरा गांव में बीती रात चोरों ने एक बंद कमरे का ताला तोड़कर नकदी व लाखों रुपये कीमत के आभूषण पार कर दिए। विरोध करने पर गृहस्वामी को ईट पत्थर से मारकर घायल कर मौके से भाग निकले उक्त गांव निवासी राम मूरत यादव के तीन कमरे के मकान में दो कमरो में परिजन सो रहे थे जबकि एक कमरे में ताला बंद था। देर रात करीब ढाई बजे चोरों ने ताला तोड़कर बक्से में रखे पांच हजार रुपये नकद व लाखों रुपये के जेवरात चोरी कर रहे थे खटपट की आवाज सुनकर राम मूरत की नींद टूटी और उन्होंने शोर मचाया। इसी दौरान चोरों ने ईंट से वार कर उन्हें घायल कर दिया और मौके से भाग निकले घटना की सूचना पीड़ित ने डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और लौट गई। मंगलवार सुबह राम मूरत ने थरवई थाने में प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार पांडे को लिखित तहरीर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

भिवंडी में खाद माफिया पर बड़ी कार्रवाई, 78 लाख की यूरिया जब्त

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी तालुका में कृषि विभाग और पडघा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए खाद माफियाओं के गोरखधंधे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कुरुंद गांव स्थित एक गोदाम से 2668 बैग में रखे 78 लाख 11 हजार 736 रुपये मूल्य के सब्सिडी वाले यूरिया खाद का अवैध स्टॉक जब्त किया है। इस मामले में कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर पडघा पुलिस स्टेशन और ठाणे ग्रामीण अपराध शाखा की टीम ने मुंबई-नासिक राजमार्ग पर भोईरपाड़ा गांव के पास जाल बिछाकर दो ट्रकों (क्रमांक K.A.16/AA/4849 Deewj K.A.16/AA/4846) को रोका। जांच में पता चला कि कृषि उपयोग के लिए निर्धारित यूरिया को औद्योगिक उपयोग हेतु सफेद बोरियों में दोबारा पैक किया जा रहा था।सूचना की पुष्टि होते ही कृषि विभाग के अधिकारी और गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक मौके पर पहुंचे। इसके बाद कुरुंद स्थित वेअर-स्क्वायर लॉजिस्टिक पार्क के गोदाम क्रमांक 3-8 पर छापा मारा गया। यहां री-पैकिंग की बड़ी खेप बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि मौके से 9 मजदूर और 3 ट्रक चालकों को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी में 1217 बोरे यूरिया (कीमत 35 लाख 90 हजार रुपये), खाली पीली-सफेद बोरियां, सिलाई मशीन, नायलॉन रस्सी और दो ट्रक समेत कुल 1 करोड़ 28 लाख 31 हजार 736 रुपये का माल जब्त किया गया है। कृषि अधिकारी की शिकायत पर पडघा थाने में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

बदनाम करने की धमकी देकर महीनों तक यौन शोषण, आरोपी गिरफ्तार

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। अपनी पहचान का फायदा उठाकर एक शख्स ने एक 34 साल की महिला का महीनों तक यौन शोषण किया। आरोपी ने महिला की निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर उसे लगातार प्रताड़ित किया। आरोपी ने अक्टूबर 2024 से अब तक महिला के साथ अलग-अलग जगहों पर कई बार जबरन संबंध बनाए और विरोध करने पर मारपीट और गाली-गलौज भी की। पुलिस ने महेश गणेश गोपी उर्फ ??पिट्या (32) नामक व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1)64(2)(ड),115(2),353,351(1) के तहत केस दर्ज किया है।

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, आरोपी महेश और पीड़िता एक ही इलाके में रहते हैं। दोनों की जान-पहचान शिवाजी चौक पर हुई थी। इस जान-पहचान का फायदा उठाकर आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उसकी कुछ निजी तस्वीरें और वीडियो भी बना लिए। इसके बाद, आरोपी ने इन तस्वीरों और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर महिला का यौन शोषण करना शुरू कर दिया। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी महेश महिला को वाजेश्वरी और गणेशपुरी के अलग-अलग कमरों में ले जाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता था। जब महिला इसका विरोध करती थी तो आरोपी उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज करता था। हाल ही में, आरोपी ने एक बार फिर जबरन शारीरिक संबंध बनाने के बाद महिला के कपड़े पहनते समय उसके फोटो और वीडियो बनाए। उसने महिला को धमकी दी कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगी तो इन तस्वीरों और वीडियो को वायरल कर देगा।इस प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने निज़ामपुरा पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

जिला नियोजन समिति के अंतर्गत कार्य गुणवत्तापूर्ण और समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाने चाहिए- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई। जिला नियोजन समिति के माध्यम से किए जाने वाले सभी विकास कार्यों को गुणवत्ता और मानक बनाए रखते हुए एक निश्चित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। यदि विकास कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाते हैं, तो जिले का समग्र विकास संभव है। प्रत्येक योजना को नागरिकों तक प्रभावी ढंग से पहुँचाया जाना चाहिए और जिले को सभी सतत विकास लक्ष्यों में अग्रणी रखा जाना चाहिए, ऐसा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा।

मुंबई शहर जिला नियोजन समिति की बैठक उपमुख्यमंत्री और मुंबई शहर जिले के संरक्षक मंत्री तथा जिला नियोजन समिति के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर परिसर के सेंट्रल हॉल में आयोजित की गई। बैठक में कौशल, उद्यमिता, रोजगार और नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट शामिल हुए। राहुल नार्वेकर, मुंबई नगर निगम आयुक्त भूषण गगरानी, मुंबई शहर की जिला कलेक्टर आंचल गोयल सहित सभी जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जिला वार्षिक योजना 2025-2026 में सामान्य योजना के अंतर्गत 528 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत 22 करोड़ रुपये और अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत 553 करोड़ रुपये का बजट है। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने बैठक में निर्देश दिया कि जिला वार्षिक योजना की राशि स्वीकृत योजनाओं और कार्यों पर निर्धारित समय सीमा के भीतर खर्च की जाए।

वर्ष 2024-2025 के लिए व्यय का अनुमोदन

जिला वार्षिक योजना 2024-2025 में कुल 509 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष व्यय हुआ है, जिसमें सामान्य योजना के अंतर्गत 487.03 करोड़ रुपये और अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत 22 करोड़ रुपये शामिल हैं, और इस बैठक में इस व्यय को मंजूरी दी गई।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई शहर जिले में रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एसआरए, एमएमआरडीए, सिडको, नगर निगम, म्हाडा जैसी एजेंसियों को समन्वय से काम करना चाहिए, ऐसा उपमुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा।

सरकार का काम आम लोगों को न्याय दिलाना है और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाना चाहिए। नागरिकों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सकें, इसके लिए हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे ने अपना क्लिनिक शुरू किया है। मनपा अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले आम मरीजों के लिए मनपा अस्पताल में एक एमआरआई मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि चूँकि मुंबई एक विश्वस्तरीय शहर है, इसलिए स्वच्छता बनाए रखने, प्रदूषण कम करने और वृक्षारोपण जैसी गतिविधियाँ कार्यान्वित की जा रही हैं।

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने मनपा प्रशासन को निर्देश दिया कि मानसून के बाद गड्ढों को भरने का काम तुरंत शुरू किया जाए ताकि मुंबई शहर के सभी फ्लाईओवर गड्ढों से मुक्त हो जाएँ। साथ ही, नगर निगम के संबंधित अधिकारी शहर में पेयजल की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने पर ध्यान दें। शहर के पार्कों का विकास नागरिकों को अच्छा वातावरण प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए। इन पार्कों की आवश्यक मरम्मत का कार्य प्राथमिकता से किया जाना चाहिए।

'जिला 2028 तक सामाजिक और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करके रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य रखता है ताकि जिले को सभी सतत विकास लक्ष्यों में अग्रणी रखा जा सके। चयनित क्षेत्र मत्स्य पालन, रत्न और आभूषण, चमड़ा, पर्यटन, स्वास्थ्य, परिवहन, रियल एस्टेट हैं। जिले का सकल घरेलू उत्पाद 2028 तक 1,52,753 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,51,361 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

योगी का संकल्पः भारतीय श्रम-प्रतिभा से बने हर उत्पाद को दें बढ़ावा, यह राष्ट्रीय गौरव है

लखनऊ। स्वदेशी उत्पादों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को नागरिकों से भारतीय प्रतिभाओं का समर्थन करने और स्वदेशी कारीगरों द्वारा निर्मित उत्पाद खरीदने का आग्रह किया। 'आत्मनिर्भर भारत-स्वदेशी संकल्प' पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री योगी ने उत्पादन में आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संदेश है कि हमें भारतीय कारीगरों के श्रम और हमारे युवाओं की प्रतिभा से बनी हर चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने इस आह्वान को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ते हुए कहा कि सदियों से विदेशी आक्रमणों के कारण भारत की जनसंख्या और कृषि को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू आबादी, जो उनके अनुमान के अनुसार वर्ष 1100 तक लगभग 60 करोड़ थी, 1947 में स्वतंत्रता के समय तक घटकर लगभग 30 करोड़ रह गई थी। उन्होंने पूछा, 'वर्ष 1100 तक भारत में हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी। और जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, तब हिंदुओं की आबादी सिर्फ़ 30 करोड़ थी। बताइए, इन 800-900 सालों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी या घटनी चाहिए थी?'

योगी ने कहा इसका मतलब है कि न सिर्फ़ आबादी घटी, बल्कि हमारा कृषि उत्पादन भी कम हुआ। यह घटती आबादी न सिर्फ़ आक्रांताओं द्वारा मारी गई, बल्कि भूख, बीमारी और तमाम तरह की यातनाओं से भी मरी। विदेशी गुलामी ऐसे ही होती है। इस देश पर भी यही सब कुछ थोपा गया। इस देश पर अत्याचार और शोषण किया गया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सब कुछ होते हुए भी भारत को विदेशी शासकों द्वारा किए गए विभाजन का खामियाजा भुगतना पड़ा। इससे पहले सोमवार को, जब देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 2.0 लागू हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों को एक पत्र लिखा, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि 'जीएसटी बचत उत्सव' से बचत को बढ़ावा मिलेगा और समाज के हर वर्ग को सीधे लाभ होगा। अपने पत्र में पीएम मोदी ने देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दीं।

'10 हजार शब्दों का शब्दकोश तैयार', सांकेतिक भाषा पर मंत्री बोले- दिव्यांगों को अवसर देना जरूरी

नई दिल्ली। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने मंगलवार को कहा कि विकलांग बच्चों को पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि समावेशन केवल सरकार की कोशिशों से संभव नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक और शैक्षिक संगठनों की भी अहम भूमिका है। वे भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित सांकेतिक भाषा दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री ने कहा कि भारतीय सांकेतिक भाषा को मजबूत करने के प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के विज़न को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि विकलांग बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, उन्हें सिर्फ अवसरों की जरूरत है।

आईएसएलआरटीसी की उपलब्धियां

वीरेंद्र कुमार ने बताया कि आईएसएलआरटीसी ने अब तक 10,000 शब्दों की सांकेतिक भाषा शब्दकोश तैयार किया है, 2,300 से ज्यादा वीडियो बनाए हैं और नए डिप्लोमा व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए हैं, ताकि शिक्षक और दुभाषियों को प्रशिक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से छात्रों को नए शैक्षिक रास्ते मिलेंगे और शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने की दिशा में बड़ी प्रगति होगी।

प्रेरणादायक उदाहरण और भावुक क्षण

मंत्री ने हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा देहरादून स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड की यात्रा का ज़िक्र किया। यहां दृष्टिबाधित बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए जन्मदिन गीत गाया था। मंत्री ने कहा कि इन बच्चों की मीठी आवाज़ से राष्ट्रपति भावुक हो गए थे। यह उदाहरण बताता है कि यदि कुछ कमी है, तो ईश्वर ने अन्य क्षमताओं से बच्चों को विशेष बनाया है।

समावेशन में समाज की भूमिका अहम

कुमार ने स्पष्ट किया कि समावेशन केवल सरकार के प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए सामाजिक और शैक्षिक संस्थानों की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि चाहे किसी क्षेत्र में बच्चों की संख्या अधिक हो या कम, सभी को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण का समान लाभ मिलना चाहिए।

'सबका साथ, सबका विकास' से जुड़ी सोच

प्रधानमंत्री मोदी के विकास एजेंडे का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का अर्थ है कि विकलांग बच्चों को भी पीछे नहीं छोड़ा जाए। वे भी आत्मनिर्भर बनें और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान दें।

'सुपर स्वच्छ नवी मुंबई - स्वच्छ संवाद' पहल में 35 हज़ार से ज़्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया और स्वच्छता का संकल्प लिया

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

चूँकि स्वच्छता एक नियमित प्रक्रिया है, इसलिए नवी मुंबई नगर निगम विभिन्न माध्यमों से लगातार जागरूकता पैदा कर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन द्वारा घोषित 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के तहत 17 नवंबर से विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं और जनभागीदारी पर ज़ोर देकर व्यापक जनजागृति भी की जा रही है। इसमें देश के भविष्य कहे जाने वाले छात्रों के मन में कम उम्र से ही स्वच्छता का संस्कार डाला जाना चाहिए ताकि नई पीढ़ी स्वच्छता के प्रति आग्रही बने, और स्वच्छता गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी पर ज़ोर दिया जा रहा है।

इसी तरह की एक अभिनव पहल, 'सुपर स्वच्छ नवी मुंबई - स्वच्छ संवाद', नगर आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे के मार्गदर्शन में स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के अंतर्गत 'फेसबुक लाइव वेबिनार' के रूप में क्रियान्वित की गई। नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र के 70 से अधिक नगरपालिका और निजी स्कूलों के 35,000 से अधिक छात्रों ने इसमें भाग लिया।

इन छात्रों ने स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट पृथक्करण, कचरे के उचित निपटान और सोशल मीडिया व एआई के उचित उपयोग के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। नवी मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय स्थित नॉलेज सेंटर सभागार में आयोजित इस इस वेबिनार में चार एनिमेटेड शुभंकर, अर्थात् गीले कचरे के लिए 'ओलू', सूखे कचरे के लिए 'सुकु', घरेलू खतरनाक कचरे के लिए 'घटकू' और स्वच्छता कचरे के लिए 'सानू', ने छात्रों को

गतिविधि में 200 से अधिक छात्रों और 25 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया, जबकि 35,000 से अधिक छात्रों ने अपने-अपने स्कूलों से फेसबुक लाइव के माध्यम से भाग लिया। इस अवसर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग के उपायुक्त डॉ. अजय गाडे, शिक्षा अधिकारी श्रीमती सुलभा बरघरे सभागार में उपस्थित थीं।

स्वच्छता और कचरा पृथक्करण के बारे में मनोरंजक और सरल तरीके से जानकारी प्रदान की। इसी प्रकार, खाद्य अपशिष्ट, पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट, अस्वीकृत अपशिष्ट और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। छात्रों के साथ सीधे ऑनलाइन संवाद के माध्यम से, समय-समय पर उनकी शंकाओं का समाधान किया गया और स्वच्छता संबंधी प्रश्न पूछकर उन्हें संवाद में सक्रिय रूप से शामिल किया गया। वर्तमान युग अत्याधुनिक एआई तकनीक के प्रभुत्व में है और एआई क्या है और यह स्वच्छता के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, इस पर प्रदर्शनों के साथ-साथ सरल भाषा में जानकारी दी गई। छात्रों से अपनी प्रगति के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने और सोशल मीडिया के माध्यम से स्वच्छता को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया गया।

छात्रों को यह भी बताया गया और प्रोत्साहित किया गया कि वे एआई और सोशल मीडिया की मदद से 'स्वच्छता प्रभावक' कैसे बन सकते हैं। छात्रों से उनके द्वारा बनाए गए एआई पोस्टरों को हैशटैग क्स्श्णएप2025 के साथ सोशल मीडिया पर साझा करने का भी आग्रह किया गया। छात्रों को यह भी बताया गया कि नवी मुंबई नगर निगम द्वारा छात्रों द्वारा अपलोड की गई सर्वश्रेष्ठ सामग्री को नगर निगम के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा। छात्रों को प्लास्टिक कचरे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देते हुए, प्लास्टिक कचरा और ई-कचरा पहल के बारे में जानकारी दी गई, जिसे नवी मुंबई नगर निगम पिछले दो महीनों से प्रोजेक्ट मुंबई के सहयोग से लागू कर रहा है। स्वच्छता संवाद कार्यक्रम में प्रोजेक्ट मुंबई के प्रतिनिधियों ने एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध, प्लास्टिक पुनर्चक्रण और प्लास्टिक कचरे से उत्पाद बनाने जैसे विभिन्न विषयों पर प्रस्तुति दी। प्लास्टिक कचरे से बने पुनर्चक्रित उत्पादों का भी प्रदर्शन किया गया। छात्रों के शैक्षणिक समय को बाधित किए बिना घरेलू प्लास्टिक संग्रहण हेतु एक विशेष पहल लागू करने की अवधारणा प्रस्तुत की गई। इस पहल में शिक्षकों को भी इसमें पहल करने का सुझाव दिया गया और प्रत्येक छात्र से नवी मुंबई का सुपर स्वच्छता नायक बनने की अपील की गई।

25 सितंबर 2025 को, स्वच्छ भारत मिशन ने एक दिन, एक साथ, एक घंटा की एक अनूठी सामूहिक श्रम पहल लागू करने की घोषणा की और तदनुसार, छात्रों सहित प्रत्येक नागरिक से 25 सितंबर को सुबह 1 घंटे के लिए अपने स्कूलों और अपने आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की गई। 'सुपर स्वच्छ नवी मुंबईचा स्वच्छ संवाद' पहल के माध्यम से, नवी मुंबई नगर निगम क्षेत्र के निजी और नगरपालिका स्कूलों के 35 हजार से अधिक छात्रों ने अपने मन में स्वच्छता का संदेश बिठाकर सुपर स्वच्छ नवी मुंबई की प्रतिष्ठा में योगदान देने की शपथ ली।

मुख्य न्यायाधीश गवई बोले- बुलडोजर कार्रवाई पर दिए फैसले से मिली थी 'बेहद संतुष्टि'

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने हाल ही में एक कार्यक्रम में बताया कि है उन्हें बुलडोजर कार्रवाई पर दिए गए अपने फैसले से 'बेहद संतुष्टि' मिली थी, क्योंकि यह सीधे-सीधे 'मानवीय समस्याओं' से जुड़ा हुआ था। बता दें कि 13 नवंबर, 2024 को जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने बुलडोजर न्याय की तुलना एक ऐसी अराजक स्थिति से की जहां ताकत ही सही है और अखिल भारतीय स्तर पर दिशा-निर्देश निर्धारित किए। सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ में न्यायमूर्ति गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन शामिल थे।

19 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के एक शैक्षणिक समूह द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि उन्हें लगभग छह महीने तक जस्टिस विश्वनाथन के साथ पीठ साझा करने का अवसर मिला। इस दौरान खंडपीठ ने अभियुक्तों/दोषियों की

संपत्तियों को मनमाने ढंग से ध्वस्त करने की कार्यपालिका की प्रवृत्ति के खिलाफ कई निर्देश पारित किए।

'इस फैसले के लिए श्रेय न्यायमूर्ति विश्वनाथन को भी दिया जाना चाहिए'

गवई ने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि बुलडोजर वाला फैसला, हम दोनों के लिए बेहद संतोषजनक था। इस फैसले के मूल में मानवीय समस्याएं और इंसानों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं थीं। जिस परिवार को सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा था क्योंकि वे ऐसे किसी सदस्य जो अपराधी था, उसके परिवार का हिस्सा थे। सीजेआई ने कहा कि हालांकि इसका अधिकतर श्रेय उन्हें ही दिया जाता है लेकिन फैसला लिखने वाले जस्टिस विश्वनाथन को भी बराबर श्रेय दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल का न्याय प्रशासन की दक्षता से कोई सीधा संबंध है। हमारे पास ढाई महीने तक न्यायमूर्ति ललित और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जैसे सर्वश्रेष्ठ मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है और वे न्याय के वितरण और प्रशासन में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। गवई ने कहा कि उन्होंने न्याय की बेहतरी और पूरे देश में न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया।

सीजेआई के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे युवा वकीलों को अच्छा प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा, हम सभी आश्वस्त हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जो समृद्ध अनुभव प्राप्त होता है, वह वास्तव में हाईकोर्ट स्तर पर दक्षता लाने या उसे बढ़ाने में मदद करता है।

जस्टिस वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच तेज, नकदी मामले में समिति की मदद करेंगे दो वकील

नई दिल्ली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच तेज हो गई है। नकदी मामले की जांच कर रही समिति की मदद के लिए दो वकीलों को नामित किया गया है। समिति की सहायता के लिए रोहन सिंह और समीक्षा दुआ को सलाहकार नियुक्त किया गया है।

पिछले महीने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए राजनीतिक दलों का नोटिस स्वीकार किया था। 14 मार्च को वर्मा के सरकारी आवास पर नोटों की जली हुई गड्डियां पाई गई थीं।

लोकसभा अध्यक्ष ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य की एक समिति गठित की थी।

अब समिति की मदद के लिए दो वकीलों की नियुक्ति की गई है। दोनों नियुक्तियां समिति के कार्यकाल के साथ या अगले आदेश तक जारी रहेंगी।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने की सिफारिश की गई थी

इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने 7 अगस्त, 2025 को कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने की सिफारिश करने वाली आंतरिक जांच प्रक्रिया को कानूनी मान्यता प्राप्त है।

जस्टिस वर्मा के आवासीय परिसर में आग लगने के बाद जले हुए नोट मिले थे। उस समय वे दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे।

तीन न्यायाधीशों के पैनल ने जांच की थी

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाले तीन न्यायाधीशों के पैनल ने मामले की 10 दिनों तक जांच की। इस दौरान 55 गवाहों से पूछताछ की गई और 14 मार्च की रात लगभग 11.35 बजे न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास पर लगी आकस्मिक आग वाले घटनास्थल का दौरा किया। जस्टिस वर्मा उस समय दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कार्यरत हैं।

डब्ल्यूएफआई ने अमन सहरावत को जारी किया कारण बताओ नोटिस, 27 तक देना होगा जवाब

नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती महासंघ ने सोमवार 22 सितंबर 2025 को पेरिस ओलंपिक के ब्रान्ज मेडल विजेता अमन सहरावत को वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वीकार्य वजन सीम पर खरा नहीं उतर पाने के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया। अमन पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती 57 किलोग्राम स्पर्धा में पदक के प्रबल दावेदारों में से एक थे, लेकिन प्रतियोगिता के दिन उनका वजन 1.7 ज्यादा निकला। जिस कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।

डब्ल्यूएफआई ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि जगरेब में चार कोच मौजूद थे, लेकिन वे वजन प्रबंधन पर नजर नहीं रख पाए और इसके मद्देनजर उन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक पदाधिकारी ने बताया कि ये स्वीकार्य नहीं है। हमें इसके पीछे के कारणों का पता लगाना

होगा। दो महीने से भी कम सयम में हमारे दो अच्छे पहलवानों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। हमें इसकी जांच करनी होगी इसलिए हमने अमन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डब्ल्यूएफआई के पदाधिकारी ने बताया कि मुख्य कोच जगमंदर सिंह, विनोद, वीरेंद्र और नरेंद्र को भी स्पष्टीकरण देना होगा। उन्होंने बताया कि अमन और चारों कोच से 27 सितंबर तक जवाब देने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि वहां 10 पहलवान और चार कोच थे। उन्हें इस मद्दे पर ध्यान देना चाहिए था। वे प्रतियोगिता से 15 दिन पहले वहां थे। ये उनकी भी जिम्मेदारी थी इसलिए उन्हें भी स्पष्टीकरण देना होगा।

ऑस्ट्रेलिया की मशहूर लीग में खेलते नजर आएंगे अश्विन, बन सकते हैं पहले कैप्ड भारतीय

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन, बिग बैश लीग (बीबीएल) में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय कैप्ड खिलाड़ी बन सकते हैं। बीबीएल के चार क्लब आगामी सत्र के आखिरी चरणों के लिए उनकी सेवाएं लेना चाहते हैं। इन टीमों के नाम सिडनी थंडर, सिडनी सिक्सर्स, ऐडिलेड स्ट्राइकर्स और होबार्ट हरिकेंस हैं, जिसमें थंडर और हरिकेंस दौड़ में सबसे आगे हैं। इस सप्ताह के अंत तक यह डील फाइनल हो सकता है।

भारत का कोई भी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अब तक बीबीएल में नहीं खेला है। बीसीसीआई केवल संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को ही विदेशों की टी20 लीग्स में खेलने की अनुमति देता है। इस साल के शुरू में दिनेश कार्तिक ने यूँ20 में पार्ल रॉयल्स के लिए खेला था। इससे पहले 2023 में अंबाती रायुडू सीपीएल में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रिएट्स के लिए और फिर जनवरी 2024 में श्द एमिरेट्स के लिए आईएलटी20 में खेल चुके हैं। इसी सीजन में रॉबिन उथप्पा और युसूफ़ पठान दुबई कैपिटल्स का हिस्सा थे। वहीं दो साल पहले अबु धाबी टी10 में सुरेश रैना, डेक्कन ग्लैडिएटर्स का हिस्सा थे।

एक रिपोर्ट में पता चला है कि उनकी डील में 2026-27 का बीबीएल भी शामिल होगा। बीबीएल क्लब अपने एकदाश में केवल तीन विदेशी खिलाड़ियों को ही खिला सकते हैं। लीग के प्री-सीजन नियमों और जून के ओवरसीज ड्राफ्ट के जरिए हर

क्लब पहले ही तीन विजेशी खिलाड़ियों को लॉक कर चुका है। इसके बाद सभी क्लब अतिरिक्त चार विदेशी रिप्लेसमेंट खिलाड़ियों को साइन कर सकते हैं। यानी उनके दल में कुल सात विदेशी खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं, लेकिन एक समय में केवल तीन ही खेल सकते हैं।

लीग के आखिरी हिस्से में अगर किसी टीम ने किसी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को एसए20 के लिए रिलीज किया तो अश्विन एकादश में उनकी जगह ले सकते हैं। लीग के नियमों के अनुसार रिप्लेसमेंट विदेशी खिलाड़ियों को भी ड्राफ्ट के लिए नामांकन करना होता है, जिसे अश्विन ने तब नहीं किया था क्योंकि उस समय उन्होंने आईपीएल से संन्यास नहीं लिया था। मगर ऐसी परिस्थितियों के लिए एक छूट यह है कि यदि किसी विदेशी खिलाड़ी के लिए परिस्थिति बदल गई हो, तो उसे बीबीएल में खेलने की अनुमति दी जा सकती है। जो क्लब अश्विन को साइन करेगा, उसे अभी ही उनका वेतन, अपने ओवरऑल पर्स के भीतर फ़टि करना होगा।

अधिकांश टीमों के पर्स पहले ही आवंटित हो चुके हैं। लेकिन संभव है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ एक अतिरिक्त मार्केटिंग एग्रीमेंट होगा, जो उस टीम के सैलरी कैप में नहीं गिना जाएगा, जो भी टीम अश्विन को लेगी। टीमें एक विशिष्ट वर्ष में लीग की तकनीकी समिति की मंजूरी के साथ कैप से 5त्न अधिक भी जा सकती हैं, बशर्ते कि उसे तीन साल की अवधि में बैलेंस किया जाए।

एसएंडपी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5 फीसदी पर रखा बरकरार

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर को 6.5इ पर बरकरार रखा है। रेटिंग एजेंसी ने यह अनुमान मजबूत घरेलू मांग और अनुकूल मानसून को ध्यान में रखते हुए जारी किया है। साथ ही, एसएंडपी ने उम्मीद जताई कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर में 0.25इ की कटौती कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीआई ने इस वर्ष के लिए अपने महंगाई दर के पूर्वानुमान को 3.2इ तक घटा दिया है। अप्रैल-जून तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8इ रही थी।

एसएंडपी ने अपने बयान में कहा, 'हमारा अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष (31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाला) में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5इ बनी रहेगी। घरेलू मांग मजबूत बनी रहेगी, जिसे सामान्य मानसून, आयकर और जीडीपी में कटौती और सरकारी निवेश में तेजी का समर्थन मिलेगा।'

रेटिंग एजेंसी ने यह भी कहा कि खाने-पीने के चीजों की महंगाई दर (खाद्य मुद्रास्फीति) में अपेक्षाकृत ज्यादा कमी से महंगाई को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी और इससे मौद्रिक नीति में और समायोजन की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक चालू वित्त वर्ष में रेपो रेट में 0.25इ की कटौती कर सकता है।

एसएंडपी ने अपनी रिपोर्ट 'एशिया-प्रशांत चौथी तिमाही 2025ः बाहरी दबाव से वृद्धि में कमी' में कहा कि पूरे क्षेत्र में घरेलू मांग अपेक्षाकृत बेहतर रहने के चलते अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक आर्थिक सुस्ती के बावजूद बाहरी विपरीत हालातों का असर कम होगा। रेटिंग एजेंसी ने यह भी कहा कि जून की तुलना में अब चीन का प्रदर्शन अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर रहा है, जबकि दक्षिण-पूर्व एशियाई उभरते बाजार अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत पर अमेरिकी शुल्क का असर अनुमान से अधिक गहरा रहा है।

ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी के सामने पेश हुए युवराज सिंह सोनू सूद से 24 सितंबर को होगी पूछताछ

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारत के पूर्व स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप वर्नेबेट से जुड़े धन शोधन के मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष मंगलवार को पेश हुए। सफेद टीशर्ट और जींस पहे 43 वर्ष के युवराज दोपहर बाहर बजे एजेंसी के दफ्तर पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने इस हरफनमौला से पूछतछ की ओर धन शोधन निरोधक अधिनियम के तहत उनके बयान दर्ज किए।

एक इन्फ्लुएंसर अन्वेशी जैन भी इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश हुई। ईडी इससे पहले क्रिकेटर सुरेश रैना, शिखर धनव, रॉबिन उथप्पा, टीएमसी की पूर्व सांसद और बांग्ला अभिनेत्री मिमि चक्रवर्ती, अभिनेता अंकुश हाजरा से भी पूछताछ कर चुका है। अभिनेता सोनू सूद को बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सूत्रों के अनुसार ईडी जल्द ही इस मामले में उन लोगों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर सकता है जो ऐप की प्रचार गतिविधियों से अर्जित कथित आपराधिक आय का इस्तेमाल करते पाए गए हैं। बाद में अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा।

जेएम समूह की तीन इकाइयों ने सेबी को 3.92 करोड़ रुपए देकर मामला निपटाया

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। जेएम समूह की इकाइयों- जेएम फाइनेंशियल, जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज और जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ने पीरामल एंटरप्राइजेज के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के सार्वजनिक निर्गम में कथित अनियमितताओं के मामले का सेबी को कुल 3.92 करोड़ रुपए का भुगतान कर निपटान कर लिया है। बाजार नियामक सेबी के 19 सितंबर को जारी निपटान आदेश के मुताबिक, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड और जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने अनुचित लाभ के रूप में अर्जित क्रमशः 1.22 करोड़ और 1.33 करोड़ रुपए वापस किए।

इसके अलावा, जेएम फाइनेंशियल ने किसी भी ऋण प्रतिभूति के सार्वजनिक निर्गम में प्रबंधक के तौर पर कार्य करने पर तीन महीने के लिए स्वैच्छिक रोक लगाने पर सहमति जताई है। इसी तरह जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड किसी भी निर्गम में तीन महीने तक वितरक नहीं बनेगी जबकि जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने तीन महीने के लिए आईपीओ वित्तपोषण गतिविधियों पर प्रतिबंध को स्वीकार किया है। मामला 2023 में पीरामल एंटरप्राइजेज के एनसीडी के सार्वजनिक निर्गम से जुड़ा हुआ है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की जांच में पाया गया कि कई व्यक्तिगत निवेशकों ने सूचीबद्धता के ही दिन इन ऋण प्रतिभूतियों को बेच दिया था जिससे खुदरा शेयरधारिता काफी कम हो गई थी। सेबी ने मार्च, 2024 में जेएम फाइनेंशियल पर अंतरिम आदेश जारी किया था। जून, 2024 में उसे किसी भी ऋण प्रतिभूति के निर्गम में प्रमुख प्रबंधक बनने से रोकने से रोक दिया गया था। सेबी ने कहा था कि जेएम समूह ने अनुचित व्यापार तरीके अपनाकर समूह के रूप में मिलकर निवेशकों को लाभ सुनिश्चित किया और कुल 1.99 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया। जेएम समूह ने तथ्यों या कानून के निष्कर्षों को स्वीकार किए बगैर मामले के निपटान का प्रस्ताव रखा था। इस पर सेबी ने आदेश दिया कि आगे की किसी भी कार्रवाई को निपटान हुआ मान लिया जाए।

हर टीम के पास भारत को हराने की काबिलियत, बांग्लादेश कोच सिमंस का सुपर-4 मैच से पहले बड़ा बयान

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारत को हराना असंभव नहीं है, यह दावा बांग्लादेश के हेड कोच फिल सिमंस ने किया है। उन्होंने एशिया कप सुपर-4 में भारत से होने वाले मुकाबले से पहले बड़ा बयान दिया। श्रीलंका पर मिली जीत से आत्मविश्वास से भरी बांग्लादेश टीम अब मौजूदा विश्व चैंपियन से भिड़ने को तैयार है।

वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर और मौजूदा कोच फिल सिमंस ने साफ कहा कि भारत अजेय नहीं है। उन्होंने कहा, 'हर टीम के पास भारत को हराने की क्षमता है। यह मायने नहीं रखता कि उन्होंने पिछले चार मैचों में क्या हासिल किया। सब कुछ इस बात पर टिका है कि बुधवार को साढ़े तीन घंटे के खेल में कौन बेहतर प्रदर्शन करता है।'

सिमंस ने माना कि भारत से जुड़े मैचों का माहौल हमेशा खास होता है। उन्होंने कहा, 'भारत दुनिया की नंबर-1 टी20 टीम है। ऐसे मैचों में उत्साह अलग होता है। मैं चाहता हूं कि मेरे खिलाड़ी इस पल का लुत्फ उठाएं और चुनौती को एंजॉय करें।' दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच को लेकर सिमंस ने बल्लेबाज़ों के लिए इसे बेहतरीन बताया। उनके मुताबिक यहां टॉस का असर नगण्य होगा। उन्होंने कहा, 'मैंने 40 ओवरों में विकेट में कोई खास फर्क नहीं देखा। यहां बल्लेबाज़ों के लिए पिच शानदार है और गेंदबाज़ों को सही लाइन-लेंथ पर गेंद डालनी पड़ती है।'

सितंबर की गर्मी में दुबई और अबुधाबी में लगातार क्रिकेट खेलना आसान नहीं है। सिमंस के मुताबिक खिलाड़ी फिट हैं, लेकिन लगातार टी20 क्रिकेट खेलना किसी भी टीम के लिए शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा, 'यह उतना आसान नहीं जितना बाहर से दिखता है।'

जीडीपी नोटिस की मौद्रिक सीमा तय करने की योजना : सीबीआईसी सदस्य

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) करदाताओं पर अनावश्यक दबाव कम करने और नोटिस जारी करने में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जीएसटी मांग के नोटिस पर मौद्रिक सीमा लागू करने की योजना बना रहा है। बोर्ड के सदस्य शशांक प्रिय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। शशांक प्रिय ने उद्योग मंडल एसोचैम के एक कार्यक्रम में कहा कि सीबीआईसी जल्द ही अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को इस संबंध में निर्देश जारी करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर मांग के नोटिस केवल इसलिए जारी नहीं होंगे कि मांग की पुष्टि हो जाए। इसके लिए एक मौद्रिक सीमा तय करने की योजना है।

उन्होंने कहा, ''हम तुच्छ आधार पर नोटिस जारी करने के पक्ष में नहीं हैं। अब क्षेत्रीय कार्यालयों में न्यायसंगत फैसले सुनिश्चित किए जाएंगे और अनुचित मांग को हटाने में कोई हिचक नहीं होगी। यह एक सांस्कृतिक बदलाव है।'' सीबीआईसी करदाताओं की सुविधा के लिए जीएसटी रिटर्न प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी काम कर रहा है। पांच करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाले व्यवसायों को अब केवल ई-इनवॉइस दर्ज करना होगा और बाकी डेटा अपने-आप ही दर्ज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि क्यूआर कोड और ई-वे बिल के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला की पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स में वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन ने इस प्रस्तावित सुधार पर कहा कि नोटिस पर मौद्रिक सीमा लागू करना करदाताओं और प्रशासन दोनों के लिए लाभकारी होगा। इससे छोटे मूल्य के विवादों में अनावश्यक नोटिस जारी होने एवं मुकदमेबाजी से बचा जा सकेगा और प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। फिलहाल अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष 20 लाख रुपए की विभागीय अपील की जा सकती है जबकि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए एक करोड़ रुपए और उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के लिए दो करोड़ रुपए की सीमा निर्धारित है। नए नियम लागू होने के बाद नोटिस स्तर पर भी ऐसी सीमाएं लागू होंगी। ऐसा होने पर व्यवसायों और प्रशासन के बीच विश्वास बढ़ेगा और अनुपालन प्रणाली अधिक संतुलित होगी।

आईसीआईसीआई बैंक ग्राहकों को तोहफा, नहीं करना होगा लंबा इंतजार

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। 4 अक्टूबर 2025 से आईसीआईसीआई बैंक ग्राहकों को चेक क्लियर होने के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के नए नियमों के मुताबिक अब सेम-डे चेक क्लियरिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। बैंक ने बताया कि ईमेल और हाइलाइट चेक डिपॉजिट प्रोसेस के जरिए दो बैंकों के बीच क्लियरेंस का समय घटा दिया गया है। पहले जहां चेक क्लियर होने में 2 से 3 दिन लगते थे, वहीं अब यह प्रक्रिया 1 दिन में पूरी हो जाएगी। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने ग्राहकों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए पॉजिटिव पे फीचर का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी है।

आरबीआई पॉजिटिव पे फीचर को दो चरणों में लागू कर रही है। पहला चरण 4 अक्टूबर, 2025 से शुरू होगा। अभी तक चेक क्लियरेंस के लिए चेक को एक बैंक से दूसरे बैंक तक फिजिकली भेजा जाता था, जिससे इसमें 2-3 दिन लग जाते थे लेकिन नए फीचर में बैंक चेक को स्कैन कर दूसरे बैंक को भेजेंगे और उसकी जानकारी को तुरंत वेरिफाई किया जाएगा। सभी डिटेल्स सही होने पर आपका चेक उसी दिन या 24 घंटे के भीतर क्लियर हो जाएगा।

आईसीआईसीआई बैंक ने बताया कि 50, 000 रुपए से अधिक राशि वाले चेक पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर लागू होगी। बैंक ग्राहकों की खाता संख्या, चेक नंबर, भुगतानकर्ता का नाम, जारी करने की तारीख और राशि को दोबारा जांचेगी। इससे बैंकिंग फ्रॉड की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी।

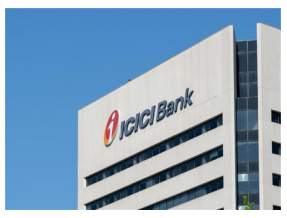

ब्रेकअप के बाद फिर आमने-सामने आए अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा, एक-दूसरे को लगाया गले

नीरज घायवान के निर्देशन में बनी और करण जौहर द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म 'होमबाउंड' पिछले काफी दिनों से चर्चा में बनी हुई है। इस मूवी को रिलीज से पहले ही 2026 ऑस्कर अवॉर्ड्स में भारत की ऑफिशियल एंट्री के लिए चुना जा चुका है। हाल ही में मुंबई में इसके प्रीमियर का आयोजन किया गया, जहां फिल्म की कास्ट जान्हवी कपूर, ईशान खट्टर और विशाल से लेकर बॉलीवुड के कई सितारें विक्की कौशल, ऋतिक रोशन से लेकर तमन्ना भाटिया तक इसमें शामिल हुए।

वहीं, सभी की निगाहें बॉलीवुड के एक्स कपल मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर पर आकर टिक गईं। दोनों का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें ब्रेकअप के बाद वह एक-दूसरे से गले मिलते हुए और बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इसे देखने के बाद यूजर्स इस पर रिएक्शन देते हुए भी नजर आ रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में अर्जुन प्रीमियर के दौरान नेहा धूपिया समेत अन्य मेहमानों के साथ बात करते हुए दिखाई दिए, जबकि मलाइका पैपराजी के लिए पोज देते नजर आईं। इवेंट में एंट्री करते ही दोनों ने एक-दूसरे से मुलाकात की। वीडियो में उन्हें 'होमबाउंड' के निर्देशक नीरज घायवान के साथ बात करते हुए भी देखा गया। दरअसल, ब्रेकअप के बाद दूरी बना कर रहे वाले एक्स कपल को एक साथ देख हर कोई हैरान रह गया। सिर्फ इतना ही नहीं, अर्जुन-मलाइका ने एक-दूसरे को गले भी लगाया। बता दें कि अर्जुन-मलाइका ने साल 2018 में डेटिंग करना शुरू किया था। शुरुआत में दोनों ने अपने रिश्ते को लोगों की नजरों से दूर रखा था। हालांकि, कुछ समय के बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी वेकेशन की साथ में रोमांटिक तस्वीरें शेयर की। फिर 2024 में दोनों के रास्ते अलग हो गए। अर्जुन ने अपनी फिल्म 'सिंघम अगेन' के प्रमोशन के दौरान इस बात को जगजाहिर किया था कि वह सिंगल हैं।

एंजेलीना जोली का बड़ा बयान, 'अब मैं अमेरिका को पहचानती ही नहीं', अभिव्यक्ति की आज़ादी पर चिंता

अमेरिकी अभिनेत्री एंजेलीना जोली ने रविवार को कहा कि वह अब अपने देश को नहीं पहचानतीं। उन्होंने स्पेन के सैन सेबेस्टियन फिल्म समारोह में अपनी नवीनतम फिल्म प्रस्तुत करते हुए अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खतरों पर चिंता व्यक्त की।

उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आलोचनात्मक मीडिया पर की गई कार्रवाई और हाल ही में रूढ़िवादी प्रभावशाली व्यक्ति चार्ली किर्क की हत्या पर टिप्पणी करने पर लेट नाइट होस्ट जिमी किमेल के शो को निलंबित करने के बाद, अमेरिका में अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।

जब जोली से पूछा गया कि क्या उन्हें अमेरिका में अभिव्यक्ति की आज़ादी का डर है, तो उन्होंने कहा, 'मुझे अपने देश से प्यार है, लेकिन इस समय मैं अपने देश को नहीं पहचानती।' उन्होंने आगे कहा, 'कोई भी चीज़, कहीं भी, जो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और आज़ादी को विभाजित करती है या सीमित करती है, और किसी से भी, मुझे लगता है कि वह बहुत खतरनाक है।' 50 वर्षीय जोली, फ्रांसीसी फिल्म निर्माता एलिस विनोकोर द्वारा निर्देशित 'कॉउचर' के प्रचार के लिए सैन सेबेस्टियन में थीं, जो महोत्सव के शीर्ष पुरस्कार, गोल्डन शेल के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है।

वह मैक्सिन वॉकर की भूमिका निभा रही हैं, जो एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक हैं और पेरिस फैशन वीक में भाग लेने के दौरान तलाक और एक गंभीर बीमारी का सामना करती हैं और फ्रांसीसी अभिनेता लुई गैरेल द्वारा अभिनीत एक सहकर्मी के साथ रोमांस शुरू करती हैं। ऑस्कर विजेता अभिनेत्री - जिन्हें 1999 में 'गर्ल, इंटरप्टेड' में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया था - ने कहा कि वह अपने नवीनतम किरदार के संघर्षों से व्यक्तिगत रूप से जुड़ी हुई हैं। जोली ने 2013 में डबल मैस्टेक्टॉमी करवाई थी और बाद में कैंसर के उच्च आनुवंशिक जोखिम को कम करने के लिए उनके अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब हटा दिए गए थे, जिससे उनकी माँ और दादी की मृत्यु हो गई थी। स्पष्ट रूप से भावुक, उन्होंने कहा कि फिल्म बनाते समय वह अक्सर अपनी माँ के बारे में सोचती थीं। जोली ने कहा, 'काश वह भी मेरी तरह खुलकर बोल पातीं, और लोग भी आपकी तरह विनम्रता से प्रतिक्रिया देते, और उन्हें अकेलापन महसूस न होता।' उन्होंने आगे कहा, 'महिलाओं के कैंसर में एक खास बात होती है, क्योंकि ज़ाहिर है यह हमें प्रभावित करता है, आप जानते हैं, कि एक महिला के तौर पर हम कैसा महसूस करती हैं।'

उत्तराखंड में सुगंध क्रांति नीति को हरी झंडीः राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा फैसला

देहरादून। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य की 'उत्तराखंड सुगंध क्रांति नीति 2026-2036' को मंज़ूरी दे दी। नीति के पहले चरण में, 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि को सुगंधित फसलों के अंतर्गत लाया जाएगा। किसानों को एक हेक्टेयर की खेती की लागत पर 80 प्रतिशत तक और एक हेक्टेयर से अधिक की लागत पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। सुगंध क्रांति नीति के अलावा, कई अन्य योजनाओं पर भी विचार किया गया और शिक्षा, आवास और कारागार के लिए विभिन्न व्यय को भी मंज़ूरी दी गई।

स्कूली शिक्षा के लिए, पीएम ई-विद्या कार्यक्रम के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, जिसके अंतर्गत वर्तमान में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) द्वारा पाँच निःशुल्क शैक्षिक टीवी चैनल प्रसारित किए जा रहे हैं, एक सुसज्जित स्टूडियो स्थापित किया जाएगा। आवास विभाग के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)

के अंतर्गत आवासों को विनिर्देशों के अनुसार संशोधित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 2,785 लाख रुपये (27 करोड़ 85 लाख 7 हजार रुपये) का अतिरिक्त अनुमानित व्यय वहन किया जाएगा। बयान में बताया गया है कि उधम सिंह नगर जिले की रुद्रपुर तहसील के बागवाला गाँव में निम्न आय वर्ग के लिए जिला विकास प्राधिकरण द्वारा 1,872 किफायती घरों का निर्माण किया जा रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में, उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद पर नियुक्ति हेतु, सितंबर 2017 से 31 मार्च 2019 के मध्य एनआईओएस द्वारा मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) के माध्यम से संचालित सेवाकालीन डी.एल.एड. प्रशिक्षण को मान्यता दी गई है।

समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न विवाह अनुदान योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति की पुत्रियों, निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों, परित्यक्त या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनाएँ और दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह हेतु अनुदान शामिल हैं, जैसा कि वक्तव्य में उल्लेख किया गया है।

'मेरी रील्स देखना बंद करो', रेखा गुप्ता का केजरीवाल पर करारा वार, बोलीं- पंजाब पर ध्यान दो

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए उनसे उनकी रीलें देखना बंद करने को कहा। यह बात उन्होंने एक दिन पहले ही साझा की थी, जब केजरीवाल ने भाजपा नेता का एक संपादित वीडियो साझा किया था, जिसमें वह चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में हेराफेरी के कांग्रेस के आरोपों पर बोल रहे थे। एक बहु-स्तरीय इलेक्ट्रिक बस डिपो की आधारशिला रखने के बाद एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि केजरीवाल को बाढ़ प्रभावित पंजाब के लोगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जहाँ उनकी पार्टी, आम आदमी पार्टी (आप), सत्ता में है।

गुप्ता ने हिंदी में कहा कि मैं केजरीवाल सर से कहना चाहती हूँ कि कृपया मेरे वीडियो, इंटरव्यू और रील देखना कम कर दीजिए। मुझे लगता है कि आप दिन भर मेरी रील देखते हैं ताकि पता चल सके कि मैडम क्या कहती हैं और क्या नहीं कहतीं। उन्होंने पंजाब का ज़िक्र करते हुए कहा कि अगर केजरीवाल ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, तो उन्हें पंजाब के लोगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वह कभी पीड़ितों के साथ नहीं दिखते। उन्होंने पंजाब का ज़िक्र करते हुए कहा, जिसने दशकों में सबसे भीषण बाढ़ का सामना किया है।

गुप्ता की यह टिप्पणी केजरीवाल द्वारा एक वीडियो साझा करने के एक दिन बाद आई है जिसमें भाजपा नेता एनडीटीवी से कांग्रेस द्वारा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में हेरफेर के आरोपों पर बात कर रहे थे। 14 सेकंड की क्लिप में, मुख्यमंत्री ने कहा, 'जब तक कांग्रेस 70 सालों तक ईवीएम में हेरफेर करती रही, तब तक तो ठीक था, लेकिन अब जब हमने ऐसा कर दिया है, तो उन्हें बुरा लग रहा है।' केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं?

'सुदर्शन चक्र होगा सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम', एयर मार्शल दीक्षित बोले- देश को देगा बहुस्तरीय सुरक्षा

नई दिल्ली। भारत अपने रक्षा कवच को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़े कदम की ओर बढ़ रहा है। प्रस्तावित एयर डिफेंस सिस्टम 'सुदर्शन चक्र' आने वाले समय में दुनिया का सबसे शक्तिशाली और व्यापक सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। यह प्रणाली ड्रोन और हाइपरसोनिक हथियारों जैसे आधुनिक खतरों से निपटने के लिए तैयार की जा रही है।

चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (सीआईएससी) एयर मार्शल अशुतोष दीक्षित ने मंगलवार को कहा कि यह प्रणाली बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान करेगी। वे 'काउंटर यूएवीज एंड एयर डिफेंस सिस्टम्सः फ्यूचर ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर' सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। दीक्षित ने बताया कि मिशन 'सुदर्शन चक्र' में काउंटर-ड्रोन, काउंटर-यूएवी और काउंटर-हाइपरसोनिक क्षमताओं को एकीकृत किया जाएगा।

युद्ध का नया स्वरूप

एयर मार्शल दीक्षित ने कहा कि युद्ध अब शतरंज की तरह है, जिसमें दुश्मन से दो कदम आगे रहना जरूरी है। उन्होंने अजरबैजान-अर्मेनिया संघर्ष और

रूस-यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे सस्ते ड्रोन महंगे सैन्य संसाधनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

एआई और तकनीकी चुनौतियां

दीक्षित ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया, जिसमें पकड़े गए ड्रोन अत्याधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस थे। उन्होंने कहा कि भविष्य की लड़ाइयों में एआई आधारित हथियार बड़ी चुनौती होंगे।

आर्थिक पहलू और आत्मनिर्भरता

दीक्षित ने कहा कि युद्ध जीतने के लिए देश को दिवालिया नहीं किया जा सकता। उन्होंने जोर दिया कि आत्मनिर्भर भारत रक्षा क्षेत्र में अनिवार्य है और काउंटर-ड्रोन सिस्टम में 'सॉफ्ट किल' और 'हार्ड किल' दोनों क्षमताएं शामिल करनी होंगी। इससे देश की ताकत बढ़ेगी और पूरी दुनिया हमारी ताकत का लोहा मानेगी।

पाकिस्तानी विमानों के भारतीय वायु क्षेत्र में घुसने पर पाबंदी बरकरार, एक महीने तक के लिए बढ़ा प्रतिबंध

नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच एयरस्पेस विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत ने सोमवार को पाकिस्तानी एयरलाइंस और विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब यह प्रतिबंध 24 अक्तूबर सुबह 5:29 बजे तक लागू रहेगा। यह फैसला भारत की एविएशन अथॉरिटी की तरफ से नया नोटिस टू एयरमेन (नोटम) जारी करके लिया गया।

लगातार छठे महीने तक एयरस्पेस प्रतिबंध जारी

इससे पहले पाकिस्तान ने दो दिन पहले ही अपने हवाई क्षेत्र को भारतीय विमानों और एयरलाइंस के लिए बंद करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान का यह नया नोटम भी 24 अक्तूबर की तारीख और समय तक के लिए प्रभावी है। इस तरह दोनों देशों के बीच एयरस्पेस प्रतिबंध अब लगातार छठे महीने में प्रवेश कर गया है।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद बढ़ा तनाव

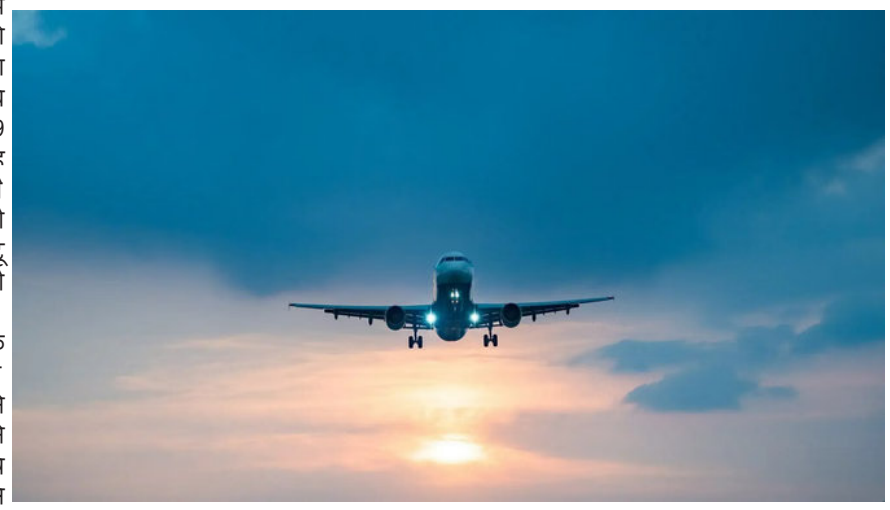

अप्रैल में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली और इस्लामाबाद के रिश्तों में तनाव गहराया था। इसके बाद पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को अचानक कदम उठाते हुए भारतीय विमानों और एयरलाइंस को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने से रोक दिया। शुरुआत में यह प्रतिबंध केवल एक महीने के लिए था। भारत ने 30 अप्रैल को जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी विमानों और एयरलाइंस, जिसमें सैन्य उड़ानें भी शामिल हैं, के लिए अपने एयरस्पेस को बंद कर दिया। तब से अब तक दोनों देश हर महीने नया नोटम जारी कर इस बंदी को लगातार बढ़ाते आ रहे हैं।

सिर्फ एक-दूसरे की उड़ानों पर रोक

बता दें कि भारत और पाकिस्तान ने यह पाबंदी सिर्फ एक-दूसरे के विमानों और एयरलाइंस पर लगाई है। उनके हवाई क्षेत्र अब भी अन्य देशों की एयरलाइंस और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए खुले हुए हैं। इसका मतलब है कि विदेशी विमान इन दोनों देशों के एयरस्पेस का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन भारतीय और पाकिस्तानी विमानों को एक-दूसरे के हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति नहीं है।

हवाई क्षेत्र का प्रतिबंध लंबे समय तक जारी रहने से न केवल एयरलाइंस की संचालन लागत बढ़ती है, बल्कि यात्रियों को भी लंबी दूरी की उड़ानों के कारण परेशानी उठानी पड़ती है। फिलहाल, भारत और पाकिस्तान दोनों के ताजा नोटम की समयसीमा 24 अक्तूबर सुबह 5:29 बजे तक तय की गई है।

'रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध की फंडिंग कर रहे भारत-चीन', संयुक्त राष्ट्र में ट्रंप का बड़ा आरोप

न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भाषण दिया। यहां ट्रंप ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम कराने का श्रेय लिया। साथ ही रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत और चीन पर बड़ा आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने टैरिफ, परमाणु हथियार, अवैध अप्रवासन समेत कई मुद्दों पर बात की।

'रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन में युद्ध की फंडिंग कर रहे चीन और भारत'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन और भारत रूसी तेल खरीद कर यूक्रेन में चल रहे रूसी युद्ध की फंडिंग कर रहे हैं। चीन और भारत रूसी तेल खरीद कर इस युद्ध को वित्तपोषित करने वाले मुख्य देश हैं।

नाटो देशों की आलोचना की, रूस को दी धमकी

ट्रंप ने कहा कि नाटो देशों ने भी रूसी ऊर्जा और रूसी ऊर्जा उत्पादों पर ज्यादा रोक नहीं लगाई है। मुझे लगभग दो सप्ताह पहले यह पता चला और मैं इससे खुश नहीं था। वे अपने ही खिलाफ युद्ध की फंडिंग कर रहे हैं। किसने इसके बारे में सुना है? अगर रूस युद्ध समाप्त करने के लिए कोई समझौता करने को तैयार नहीं होता तो अमेरिका उस पर कड़े टैरिफ़ लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मेरा मानना है कि इससे रक्तपात बहुत जल्दी रुक जाएगा। इन टैरिफ्स के प्रभावी होने के लिए यूरोपीय देशों को हमारे साथ मिलकर ठीक यही

उपाय अपनाने होंगे।

भारत-पाकिस्तान युद्ध विराम का फिर लिया श्रेय

ट्रंप ने कहा कि मैंने अपने सात महीने के प्रशासन में सात देशों में चल रहे अकल्पनीय युद्ध को समाप्त कराया। इनमें कंबोडिया-थाईलैंड, कोसोवो-सर्बिया, कांगो-रवांडा, भारत-पाकिस्तान, इस्राइल-ईरान, मिस्र और इथोपिया और आर्मेनिया-अजरबैजान शामिल हैं। यह बहुत बुरा है कि ये काम संयुक्त राष्ट्र के बजाय मुझे करने पड़े। दुख की बात है कि इन सभी मामलों में संयुक्त राष्ट्र ने इनमें से किसी में भी मदद करने की कोशिश नहीं की।

लोग चाहते हैं मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिलेः ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि हर कोई कहता है कि मुझे युद्ध विराम की उपलब्धियों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन मेरे लिए असली पुरस्कार वे बेटे और बेटियां होंगे जो अपने माता-पिता के साथ बड़े होंगे क्योंकि लाखों लोग अब अंतहीन और अपमानजनक युद्धों में नहीं मारे जा रहे हैं। मुझे पुरस्कार जीतने की नहीं, बल्कि जान बचाने की परवाह है। हमने सात युद्धों में लाखों लोगों की जान बचाई। और हमारे पास और भी हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र की आलोचना की

ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में अपार क्षमता है। लेकिन यह उस क्षमता के करीब भी नहीं पहुंच पा रहा है। कम से कम अभी तो ऐसा लगता है कि वे बस एक बहुत ही कड़े शब्दों वाला पत्र लिखते हैं और फिर उस पर अमल नहीं करते। संयुक्त राष्ट्र खोखला हो गया और खोखले शब्दों से युद्ध हल नहीं होते। संयुक्त राष्ट्र को युद्धों को समाप्त करने पर ध्यान देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र हमारे लिए नहीं है। अगर सदस्य देश इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने को तैयार हों, तो इस संगठन में काफी ताकत है।

फलस्तीन को देश का दर्जा देने का प्रस्ताव खारिज

ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन को देश का दर्जा देने का प्रस्ताव खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा कि फलस्तीनी देश को मान्यता देना हमास के लिए बहुत बड़ी बात होगी। जो लोग शांति चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होना चाहिए। गाजा में युद्ध तुरंत बंद होना चाहिए। सभी 20 बंधकों को बिना किसी देरी के रिहा किया जाए।

अमेरिका का स्वर्णिम काल चल रहाः ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत है। हमारी सीमाएं सबसे मजबूत हैं। सेना सबसे मजबूत है और दोस्ती मजबूत है। ट्रंप ने कहा कि यह अमेरिका स्वर्णिम युग है। उन्होंने कहा कि अमेरिका व्यापार करने के लिए पृथ्वी पर सबसे अच्छा देश है। अमेरिका को पहले की तरह फिर से सम्मान मिल रहा है।

परमाणु हथियार सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा, ईरान पर साधा निशाना

ट्रंप ने कहा कि परमाणु हथियार वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता।

आपदा प्रबंधन के लिए अलग-अलग मंत्रालय होंगे जिम्मेदार, तूफान से लेकर सूखा-बाढ़ तक की करेंगे निगरानी

नई दिल्ली।केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों को खास तरह की आपदाओं की जिम्मेदारी सौंपी है। यानी अब हर एक विशिष्ट आपदा की निगरानी, शुरुआती चेतावनी, रोकथाम, शमन और तैयारी की जिम्मेदारी के लिए मंत्रालय तक कर दिए गए हैं। इसके जरिए केंद्र सरकार आपदाओं के दौरान जान-माल के नुकसान को कम से कम करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 35 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए, केंद्र सरकार उन मंत्रालयों या विभागों को अधिसूचित करती है, जिन्हें अलग-अलग वजहों से पैदा हुई आपदाओं के संबंध में निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी, रोकथाम, शमन, तैयारी और क्षमता निर्माण की जिम्मेदारी दी जाएगी।'

रक्षा मंत्रालय को हिमस्खलन और तेल रिसाव की जिम्मेदारी

अधिसूचना के मुताबिक, रक्षा मंत्रालय को हिमस्खलन और तेल रिसाव जैसी आपदाओं को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। यह कदम विशेषकर सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में समय पर बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

कृषि मंत्रालय संभालेगा सूखा और कीट हमला

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को पाला, शीत लहर, सूखा, ओलावृष्टि और कीट हमले से निपटने की जिम्मेदारी दी गई है। यह कदम किसानों के हित और फसल बचाव के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जल शक्ति मंत्रालय को बाढ़ की जिम्मेदारी

जल शक्ति मंत्रालय को बाढ़ और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड से निपटने का काम सौंपा गया है। वहीं, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को शहरी बाढ़ से निपटने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन शुरुआती चेतावनी का कार्य इसमें शामिल नहीं होगा।

यूपी-गुजरात की दलहन-तिलहन फसलों की खरीद को मंजूरी, गड़बड़ी रोकने के लिए मंत्री शिवराज ने दिए निर्देश

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि-किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश और गुजरात में प्रमुख दलहन एवं तिलहन फसलों की खरीद को स्वीकृति दी है। उन्होंने किसानों से उड़द व तूर की शत-प्रतिशत खरीद के लिए मंजूरी दी है। जबकि उत्तर प्रदेश में मूंग, तिल, मूंगफली तथा गुजरात में सोयाबीन, मूंग व मूंगफली भी खरीदने की अनुमति प्रदान की है। कृषि मंत्री ने इन राज्यों को किसानों के हित में पूरी खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही कहा कि दोनों राज्यों में 13,890.60 करोड़ रुपये की उपज खरीदी से किसानों को लाभ होगा।

सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में यूपी के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही और गुजरात के कृषि मंत्री राघवजी पटेल शामिल हुए। बैठक में शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों के हित में पूरी खरीद प्रक्रिया पारदर्शी, डिजिटल व सुचारू रूप से की जाएं, जिस पर दोनों राज्यों के कृषि मंत्रियों ने कहा कि उपज खरीद आधुनिक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण व पीओएस मशीन व्यवस्था के साथ डिजिटल पोर्टलों के जरिए होगी।

बैठक में यूपी के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने राज्य में उड़द 2 लाख 27 हजार 860 मीट्रिक टन (100ड्ड) खरीद को स्वीकृति प्रदान की, जिसका मूल्य 1777.30 करोड़ रुपये रहेगा। तूर की भी शत-प्रतिशत 1,13,780 मीट्रिक टन खरीद के लिए केंद्र की ओर से शिवराज सिंह ने मंजूरी दी है, जिसकी कीमत 910.24 करोड़ रु. रहेगी। मूंग की 1983 मीट्रिक टन खरीद को मंजूरी दी गई, जिसकी कीमत 17.38 करोड़ रु. होगी। इसके अलावा, तिल की 30,410 मीट्रिक टन खरीद की स्वीकृति केंद्रीय मंत्री ने दी है, जिसकी कीमत 299.42 करोड़ रु. होगी। साथ ही मूंगफली की 99,438 मीट्रिक टन खरीद की स्वीकृति दी गई है, जिसका मूल्य 722.22 करोड़ रु. रहेगा।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने गुजरात में किसानों के लिए उड़द की पूरी 47,780 मीट्रिक टन उपज की खरीद को मंजूरी दी है, जिसकी कुल कीमत 372.68 करोड़ रुपए होगी। सोयाबीन की 1,09,905 मीट्रिक टन खरीदी की मंजूरी दी है, जिसकी कीमत 585.57 करोड़ रुपए होगी। गुजरात में मूंगफली की 12 लाख 62 हजार 163 मीट्रिक टन मात्रा खरीदने की स्वीकृति केंद्रीय कृषि मंत्री ने दी है, जिसकी कीमत 9,167.08 करोड़ रु. रहेगी। इसके अलावा, मूंग 4,415 मीट्रिक टन खरीदने की स्वीकृति शिवराज सिंह ने दी है, जिसका मूल्य 38.71 करोड़ रु. रहेगा।शिवराज सिंह चौहान ने खरीद प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता अपनाने पर जोर दिया।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 Twitter: https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 Mobile No: 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/ इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)